NOW NOIDA अपडेट

वॉल्यूम 1 | अंक 4 | April 2024

Title-Code: UPHIN51287

केजरीवाल क्यों हुए गिरफ्तार?

मोदी भाईजान

दक्षिण का दुर्ग जीतने का मोदी प्लैन

जंग जबरदस्त

गंगापुत्र Vs काशी का बेटा

Baby Bed Protector

Perfect Baby Bed Sheet Waterproof
for Ultimate Comfort

STARTING FROM ₹125

BUY NOW

sales@madebyindia.com

07011412854

www.madebyindia.com

NOW NOIDA अपडेट

सत्य से साक्षात्कार

संपादक मंडल

संपादक : संदीप ओझा

उप संपादक : पूजा मिश्रा

सहयोगी संपादक : निर्मल गौड़

नोएडा ब्यूरो चीफ : यूनुस आलम, सिल्की साहनी

वरिष्ठ संवाददाता : ओम प्रकाश सिंह

संवाददाता : साजिद अली

कला और सयंजोन : अनिरुद्ध शी, गुलशन कुमार

कानूनी सलाहकार : मौ. शाहिद, एडवोकेट

प्रबंध निदेशक : संदीप ओझा

निदेशक एवं प्रकाशक : MBI DIGITAL PVT LTD

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 99 इकोटेक 3 उद्योग केंद्र 2 ग्रेटर नोएडा 201306

मुद्रक एवं प्रकाशक : MBI DIGITAL PVT LTD प्लॉट नंबर-99, इकोटेक थर्ड, उद्योग केंद्र-2 ग्रेटर नोएडा-201306

दूरभाष- +91 120-4553364

infonownoida@gmail.com

एमबीआई डिजिटल प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सन्दीप कुमार ओझा द्वारा प्लाट नंबर-99, इकोटेक-थर्ड, उद्योग केंद्र-दो, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) से प्रकाशित व चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिग वर्क प्रा. लि. नोएडा, सी-40, सेक्टर-8 नोएडा से मुद्रित। संपादक सन्दीप कुमार ओझा (TITLE-CODE: UPHIN51287)

ग्रेटर नोएडा में फूलों का महाकुंभ	03
क्या है CAA कानून जानें क्यों हो रहा इसका विरोध	04
केजरीवाल क्यों हुए गिरफ्तार?	06

कंटेंट्स

वॉल्यूम 1 | अंक- 4 April 2024 मूल्य: ₹50

कवर स्टोरी

जंग जबरदस्त

गंगापुत्र Vs काशी का बेटा

पृष्ठ - 8

मोदी भाईजान	12
चुनावी चंदे का बही खाता चंदावीरों' के चौंकाने वाले नाम	16
भू-संपदा (विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 उत्तर प्रदेश मे इसकी यथार्थतता	19
ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पहला फुट ओवर ब्रिज, सांसद बोले- यहां के लोगों के सभी सपने होंगे पूरे	20
दक्षिण का दुर्ग जीतने का मोदी प्लैन	21

भौतिकवाद में रिश्तों का पतन	24
आदर्श आचार संहिता?	26

यमुना प्राधिकरण ने पास किया लगभग 100 अरब का बजट एयरपोर्ट, रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे पर बढ़ाया खर्च	27
व्यक्तिगत चुनाव कैसे?	28
समस्याओं से कैसे निपटेंगे डॉ. महेश शर्मा	29
गौतमबुद्ध नगर सीट, ये जातियां हैं जीत की गारंटी	30
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले "नो रजिस्ट्री, नो वोट" के लगे बैनर	32
रचेंगे इतिहास	34
आइए हम मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श से जुड़ी वर्जनाओं को मिटाएं- सीखें और जागरूक बनें	36
सांसदों का टिकट काटने में बीजेपी ने किया शतक पार	40
भारतीय लोकसभा चुनावी इतिहास	42
भारत की सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।	46
हर रंग में छुपी है खुशियों की बात...	48

संपादकीय

खतरे में लोकतंत्र, या खतरे में राजनेता ?

चुनावी बेला है। हर बात पर सियासत है। हर आदमी पैरोकार है। सबके अपने सरकार हैं। लेकिन इस राजनीति से जनकल्याण की कोई आस है। भारत के भाग्य के बदलने की कुछ उम्मीद है। रायसीना हिल्स के सिंहासन के फैसले क्या आदमी के हक और हुकूक दिला पा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की दूरदृष्टि क्या है। क्या सच में इस देश में लोकतंत्र ख़तरे में है। जैसा की हल्ला है। कि 2024 के बाद चुनाव की नौबत नहीं आएगी। 2024 के चुनावी नतीजे के बाद तानाशाही जोर चलेगा। ये शिगूफा आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है कि देश की तमाम संस्थाएं अपंग होती जा रही हैं। विचार करना होगा ऐसे तमाम विषयों पर। पहलुओं पर। गहराई में उतरकर जानना होगा हमें कि हम अफवाहों के इस दौर में सच तक कैसे पहुंचें। उस सच से हर व्यक्ति का साक्षात्कार कैसे करवाएं। NOWNOIDA के माध्यम से हम हर माह आपको सत्य से रूबरू करवाते हैं। उसी कड़ी में नवीन अंक का आरंभ छूठ की मीनार पर तनी इमारातों के धराशायी करने से कर हम कर रहे हैं। विपक्ष बराबर ये आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ED, CBI के बाद न्यायपालिका में भी खोट गिनाई जा रही है। हरीश साल्वे समेत 600 से अधिक प्रमुख वकीलों ने चिंता जाहिर की है। वकीलों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि देश में एक 'विशेष ग्रुप' न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इन सभी वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर न्यायालय और जजों का समर्थन किया है।सीजेआई को लिखे पत्र में वकीलों ने लिखा,"कानून को बनाए रखने के लिए काम करने वाले लोगों के रूप में, हम सोचते हैं कि यह हमारी अदालतों के लिए खड़े होने का समय है। हमें एक साथ आने और मौजूदा समय में न्यायालय पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ बोलने की जरूरत है।" वकीलों ने चिंता जाहिर की कि 'विशेष ग्रुप' अदालतों की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उन मुद्दों पर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, जो मामले राजनेताओं और राजनीतिक दलों से जुड़े हैं।

ये तो हाल है जिन्हें आम लोगों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है वो भी सकते में हैं। उधर राजनेताओं का भी हाल एक यही है। विपक्ष के तमाम नेताओं की कलई खुलने के बाद उनकी गिरफ्तारी और जेल जाने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, केरल के मुख्यमंत्री की बेटी जैसे न जाने कितने नाम हैं जिन पर करप्शन की कालिख लग चुकी है। चुनावी चंदे का बही खाता भी सामने हैं जिसमें सभी पार्टियां एक्सपोज हुई हैं। यानी नैतिकता के पैमाने पर कोई भी खरा नहीं उतर रहा। साफ सुथरी सियासत की कौन कहे सिर्फ खौफ का बाजार सजा है। विपक्ष मोदी का खौफ दिखा रहा है। सरकार भ्रष्ट्राचार का इश्तेहार दिखा रही है। आम आदमी के मुद्दे कहां हैं। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, रोजगार पर चर्चा की किसी के पास फुरसत नहीं। विडंबना ये भी है कि जनसामान्य ऐसी राजनीति से ऊब चुका है। ऐसे में नवचेतना की सख्त दरकार है। उम्मीद करिए कि जून महीने से इस चेतना को प्राण मिले। भारतीय लोकतंत्र पुष्पित पल्लवित रहे।

संदीप ओझा
संपादक

ग्रेटर नोएडा में फूलों का महाकुंभ

ग्रेटर नोएडा में 'पुष्पोत्सव 2024' का आयोजन सम्राट मिहिर भोज पार्क में हुआ। 8 मार्च से तीन दिन 10 मार्च तक आयोजित हुए पुष्पोत्सव को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सिटी पार्क में आयोजित पुष्पोत्सव को देखने बड़ी संख्या में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के दूसरे हिस्से से यहां पहुंचे। पुष्पोत्सव-2024 का उद्घाटन दादरी से बीजेपी के विधायक तेजपाल नागर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग के साथ फ्लोरीकल्चर सोसायटी टीम की मौजूदगी में हुआ। पुष्प प्रदर्शनी में फूलों की खेती, विशेषज्ञों से तैयार पुष्प डिजाइन, लैंड स्केपिंग, गमलों एवं स्पॉट गार्डन की सजावट आदि देखने लायक थी। तीनों दिन तक लाइव गीत-संगीत और नृत्य-कला के कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां स्कूली छात्रों और आम नागरिकों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिताएं भी हुईं।

"शहर की सुंदरता वहां की हरियाली, पार्कों की स्थिति वहां के फूल पौधों से होती है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा एनसीआर के सभी शहरों से बहुत आगे है"।

- तेजपाल नागर, *विधायक, बीजेपी*

"इस साल डहेलिया पुष्प को पुष्पोत्सव का थीम बनाया गया है, क्योंकि ये फूल बेहद खूबसूरत होता है और इसकी कई सारी वेरायटी होती है। इसके अलावा बच्चों को प्रकृति की तरफ आकर्षित करने के लिए पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया"

- अन्नपूर्णा गर्ग, *एसीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण*

"डहलिया सूरजमुखी प्रजाति का फूल है, अगर केवल नीले कलर को छोड़ दें तो डहलिया फूल की पांच हजार प्रजातियां और भिन्न-भिन्न रंगों में है। जब धूप इस फूल पर पड़ती है तो खिलकर सामने आता है। इसलिए ये फूल लोगों को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है। मास्को के इस राष्ट्रीय फूल को भारत में बेहद पसंद किया जाता है और ये भारत के वातावरण के अनुकूल भी है"

- इंदू प्रकाश सिंह, *ओएसडी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण*

क्या है CAA कानून
जानें क्यों हो रहा इसका विरोध

सिल्की साहनी
ब्यूरो चीफ

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद अब जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। CAA में छह गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो। सीएए की अधिसूचना जारी होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

सीएए कानून लागू होने के बाद देश के साथ दुनिया भर से इस पर रिएक्शन देखने को मिला। विपक्ष सीएए के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाए हुए है तो इस कानून के ऊपर पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों ने भी अपना बयान दिया है। पाकिस्तान ने सीएए को भेदभावकारी बताते हुए कहा है कि कानून धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला है। पाकिस्तान ने बकायदा बयान जारी करते कहा इस कानून से भारत के मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए से उनकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि ये नियम गलत धारणा पर आधारित है, जिसमें माना जाता है कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है और भारत अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित पनाहगार है। पाकिस्तान ने साल 2019 में भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सीएए को समानता के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया था।

सीएए पर अमेरिका ने क्या कहा

सीएए की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी, अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वो सीएए की नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित है और इस पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया कि नागरिकता संशोधन विधेयक का नोटिफिकेशन 11 मार्च को भारत ने जारी किया हम इस पर करीब से नजर रखे हुए हैं कि भारत इस कानून को किस तरह से लागू करेगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है।

क्या है सीएए?

साल 2016 में सबसे पहले (सीएए) नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया। यहां से तो ये पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक गया बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के पास नई सरकार बनी तो साल 2019 में इसे फिर से लोकसभा में पेश किया गया। इस बार ये बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पास हो गया। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद साल 2020 में ये कानून बन गया।

जानें विरोध क्यों

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह ये है कि इस कानून का विरोध करने वाले इसे एंटी-मुस्लिम बताते हैं. उनका कहना है कि जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जा रहा है? इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर सरकार का तर्क है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं और यहां पर गैर-मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है. इसी कारण गैर-मुस्लिम यहां से भागकर भारत आए हैं. इसलिए गैर-मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है. कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है. लेकिन, नागरिकता संशोधन कानून में इन तीन देशों के गैर-मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी.

केजरीवाल क्यों हुए गिरफ्तार?

यूनुस आलम,
ब्यूरो चीफ़

दिल्ली की राजनीति में इतिहास रचने वाले अरविंद केजरीवा के नाम एक ऐसा इतिहास दर्ज हुआ है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले लीडर हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह विस्तार से आप जानिए।

अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप?

ED ने अदालत में कहा है कि "आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल 'दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता" हैं। ED ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की। एजेंसी ने कहा कि 'आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता हैं। इससे पहले ED Enforcement Directorate ने एक पूरक शिकायत में, आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह-आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था। केजरीवाल ने नायर को "अपना लड़का" बताया था। आपको पता हो कि विजय नायर, आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्यूनिकेशन इंचार्ज रहे हैं।

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्ट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने दलील दी की साउथ ग्रुप से मिले करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ, वो हवाला के जरिये आया था।

क्या है साउथ ग्रुप, कौन हैं इसमें?

ED ने आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत के कुछ नेताओं और बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी ने इन्हें 'साउथ ग्रुप' के रूप में नामित किया है। साउथ ग्रुप में वाईएसआरसीपी सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे मगुंटा राघव रेड्डी, बीआरएस नेता के. कविता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरांटला, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली और एक प्रमुख फार्मास्युटिकल कंपनी के निदेशक पी सरथ कैंड्रा रेड्डी शामिल हैं।

साउथ ग्रुप से क्या कनेक्शन?

ED का दावा है कि केजरीवाल दिल्ली की विवादित आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। इस नीति को खासतौर से साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। ED का दावा है कि साउथ ग्रुप ने आबकारी नीति के जरिये जमकर लाभ लिया, थोक व्यवसायों और कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की इसके बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

केजरीवाल की दलील

अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तीन या चार नामों पर आधारित है। सिंघवी ने तर्क दिया कि मामले से जुड़े "80% से अधिक" लोगों ने केजरीवाल या उनके साथ किसी भी लेन-देन का उल्लेख नहीं किया है। सिंघवी ने कहा कि मामले को कुछ सह-अभियुक्तों और एलजी और अनुमोदकों के शब्दों से एक साथ जोड़ दिया गया है। केजरीवाल के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है। सिंघवी ने कहा, एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।

घोटाला कैसे खुला ?

जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी। जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में कथित प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया ने "मनमाने और एकतरफा फैसले लिए जिसके चलते "राजकोष को 580 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान"।

CBI और ED की जांच

मुख्य सचिव ने ये आरोप भी लगाया कि लाइसेंस शुल्क में छूट और विस्तार, जुर्माने पर छूट और कोविड-19 के कारण पैदा हुए व्यवधानों के कारण राहत के बदले आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं ने शराब व्यवसायों के मालिकों और संचालकों से रिश्वत ली। इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनावों को "प्रभावित" करने के लिए किया गया था। ये रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई और 26 फरवरी, 2023 को सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। सिसोदिया के बाद संजय सिंह। फिर के कविता और आखिर में केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए।

जंग जबरदस्त

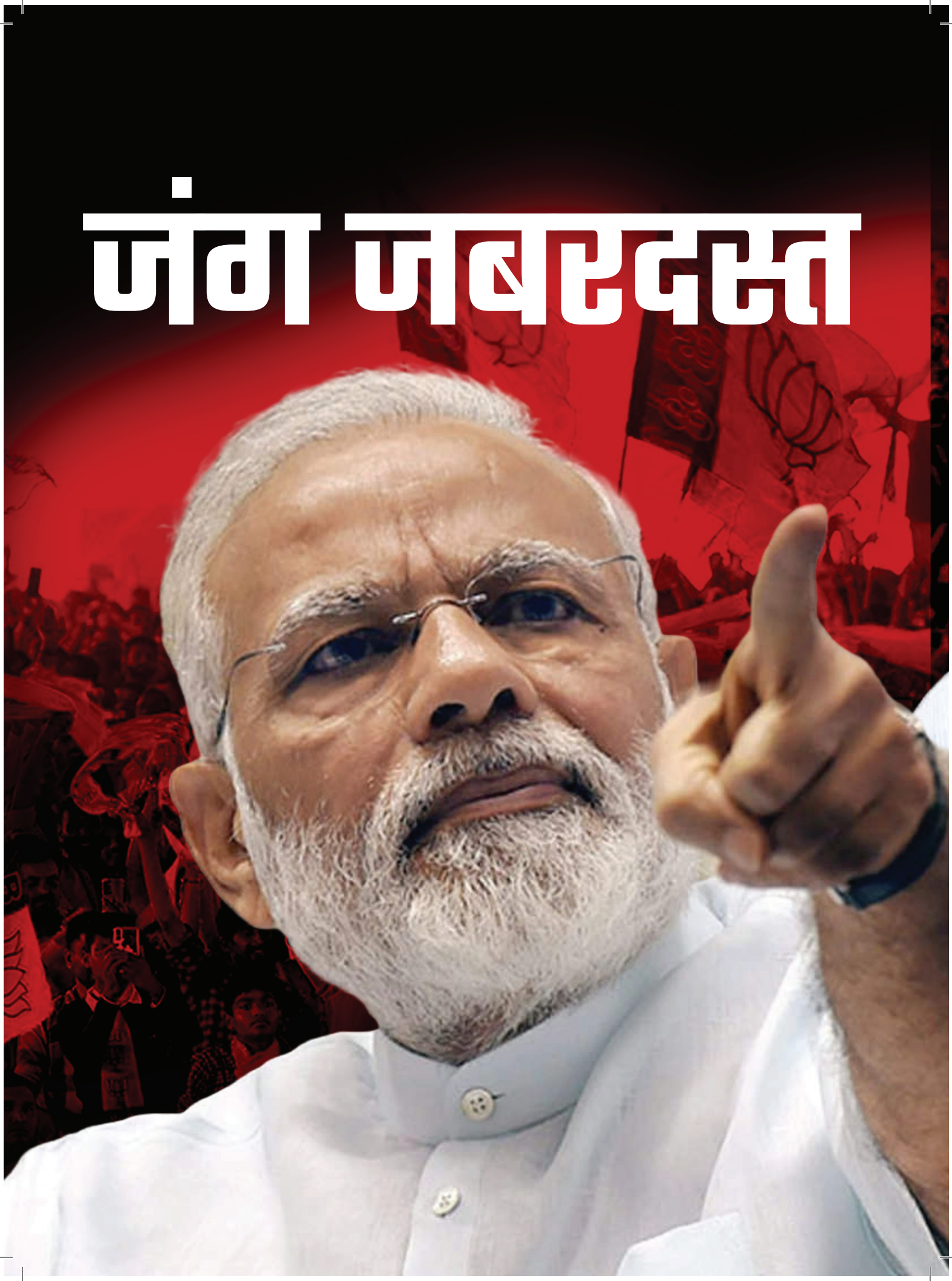

गंगापुत्र Vs काशी का बेटा

I.N.D.I.A. के अजय राय वाराणसी में PM नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे अजय राय वाराणसी सीट से जीत का दावा करते रहें हैं पिछले दो चुनावों में लगातार तीसरे स्थान पर रहे हैं अजय राय

2024 के चुनाव की सबसे हॉट सीट वाराणसी। सबसे हाईप्रोफाइल टक्कर यहीं होगी। सबको पता है यहां से नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी को काशी में अलग मुकाबलना मिलने जा रहा है। बीते 10 सालों से वाराणसी की नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में मिली है। मोदी वाराणसी से सांसद होने के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और अजय राय जैसे बड़े नेताओं को करारी शिकस्त दी। एक बार फिर वाराणसी सीट पर दुनियाभर की नजर टिकी हुई है। क्योंकि बीजेपी से नरेंद्र मोदी का मुकाबला I.N.D.I.A. गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अजय राय से होने जा रहा है।

काशी का बेटा Vs 'गांगपुत्र' मोदी ?

कांग्रेस ने अजय राय पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। I.N.D.I.A. के प्रत्याशी अजय राय सपा और कांग्रेस के साथ आने का हवाला देते हुए अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। दरअसल, विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. का गठन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हुआ है। ऐसे हालात में पीएम मोदी को वाराणसी से हराना अजय राय समेत पूरे I.N.D.I.A. के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। अजय राय खुद को काशी का बेटा कह रहे हैं। स्थानीय बता रहे हैं। लोगों से जुड़ाव की बात कर रहे है। वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में काशी से नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने कहा था, गंगा मैया ने बुलाया है। पिछले 10 सालों में वे बनारसी अंदाज में खुद को ढालने में कामयाब रहे हैं। वो भी खुद को काशी का बेटा कहकर ही संबोधित करते हैं। ऐसे में ये चुनावी जंग दिलचस्प हो गई है। चुनाव के सबसे आखिरी चरण में होने वाले मतदान को लेकर अभी से पूरे पूर्वांचल में माहौल बन गया है।

तीन बार, तीसरी पायदान

वाराणसी लोकसभा सीट के पिछले चुनावी नतीजों की बात करे तो कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय वाराणसी से चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगातार तीन लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को बुरी तरह शिकस्त दी थी। 2019 में अजय राय 5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में अजय राय को 1 लाख वोट भी नहीं मिले थे। 2014 में अजय राय को मात्र 75,614 वोट मिले थे। यानी, अजय राय अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। इतना ही नहीं, 2009 लोकसभा चुनाव में अजय राय ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा

पीएम नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में काशी से नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने कहा था, गंगा मैया ने बुलाया है। पिछले 10 सालों में वे बनारसी अंदाज में खुद को ढालने में कामयाब रहे हैं

अजय राय के मुताबिक चुनावी माहौल भी बिल्कुल बदल चुका है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बीजेपी के विकास के झूठे दावों से त्रस्त है

था। उस चुनाव में भी अजय राय बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गए थे। हाल ये हुआ कि अजय राय माफिया मुख्तार अंसारी से भी नीचे रहे थे। तीनों लोकसभा चुनाव में अजय राय तीसरे पोजिशन पर रहे थे।

गठबंधन से बदला गणित?

वाराणसी में बीजेपी अब पहले की अपेक्षा और मजबूत हो चुकी है। इसकी सबसे मुख्य वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बढ़ता ग्राफ है। पीएम मोदी के पूरे हो रहे 10 साल के कार्यकाल से प्रेरित होकर सपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के साथ आ चुके हैं। इसमें सपा की शालिनी यादव और कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का नाम शामिल हैं। दोनों नेता वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। शालिनी यादव ने 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा था। वहीं, राजेश मिश्रा 2004 में वाराणसी से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। हालांकि, 1999 और 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार राजेश मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था।

अजय राय के दावे में कितना दम?

अजय राय बनारस में I.N.D.I.A. और NDA के बीच सीधा मुकाबला मानते हैं। मोदी से वनन-टू-वन की लड़ाई में समीकरण भी बदल गया है। अजय राय के मुताबिक चुनावी माहौल भी बिल्कुल बदल चुका है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बीजेपी के विकास के झूठे दावों से त्रस्त है। वो इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि पिछले कई चुनावों में ऐसा देखने को मिला है कि भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ-साथ कोई तीसरा मजबूत उम्मीदवार भी खड़ा हो जाता था। इसकी वजह से वोट बंटवारा हो जाता था। मगर इस बार I.N.D.I.A और NDA के बीच सीधा मुकाबला है। जिससे चुनाव में इंडिया जीतेगा।

हैट्रिक तय?

चुनावी पंडित मानते हैं कि वाराणसी ही नहीं, देश भर की किसी भी सीट पर पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी I.N.D.I.A. के कैंडिडेट को हराकर काशी से जीत की हैट्रिक मार सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछले दो चुनावों के नतीजों को देख ले तो सपा कांग्रेस का टोटल वोट पीएम मोदी के वोट से भी आधा है। ऐसे में अगर ये दोनों दल एकजुट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है? जब दोनों दलों के बड़े नेता बीजेपी के साथ आ चुके हैं। बीजेपी पहले की तुलना में अब ज्यादा मजबूत भी हो गई है। तो मोदी की हैट्रिक भी तय है।

पूजा मिश्रा
उपसंपादक़

मोदी भाईजान

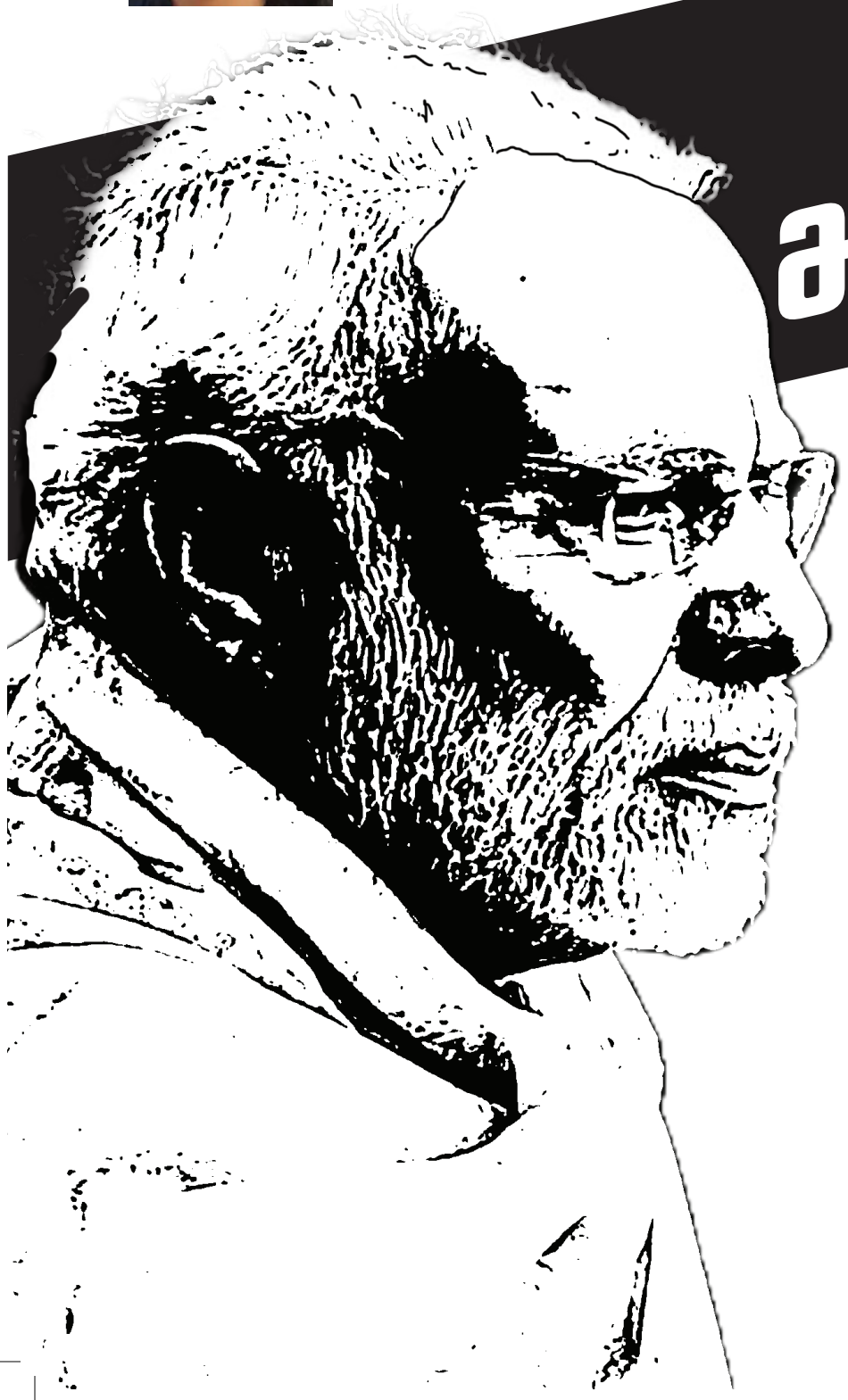

अयोध्या में बनकर तैयार भगवान रामलला का मंदिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की दशकों पुरानी हसरत के पूरा होने का प्रमाण है। आस्था के समंदर में भावनाओं का ऐसा ज्वार जिसमें पूरा देश गोते लगा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक है। माना जा रहा है कि राम मंदिर मुद्दे का बीजेपी को 2024 के चुनाव में बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन मोदी राम के साथ देश के मुसलमानों को भी अपने पाले में लाकर खड़ा करने में कामयाब हो रहे हैं। मोदी मुस्लिमों के भाई जान कैसे बन रहे हैं इसे विस्तार से समझते हैं।

मोदी के राम, देश के मुसलमान

अहमदाबाद की सड़कों पर पर जब यूएई के राष्ट्रपति के साथ मोदी के रोड शो का काफिला निकला तो सिर्फ देश के मुसलमानों को ही संदेश नहीं गया बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज गया कि मोदी ने मुसलमानों का भरोसा जीत लिया है। ये मौका वाइब्रेंट गुजरात समिट का था जब दुनिया भर से मेहमान गुजरात पहुंच रहे थे और उनके स्वागत में पूरा गांधीनगर रोशनी से नहाया हुआ था।

'मुसलमानों पर गलत बयानबाजी न करें'

देश के प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ और सबका विकास वाले नारे की बात करते हैं। ठीक एक साल पहले पीएम मोदी ने अपनी पार्टी से साफ-साफ कहा था कि मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी न करें। पसमांदा मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाएं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा था कि मुसलमान हमको वोट दें या न दें लेकिन संपर्क सबसे बनाएं।

भारत में कितने मुसलमान?

2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की कोशिश अपने लिए नया वोट बैंक बनाने की है और इसी कड़ी में पार्टी पिछड़े मुस्लिमों को साधने की कोशिश में जुट गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17 करोड़ मुस्लिम हैं। मौजूदा वक्त में देश में मुसलमान करीब 20 करोड़ हैं। जिसमें पसमांदा मुसलमान करीब 85 फीसदी हैं। यानि 15 करोड़ से ज्यादा हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमांदा मुसलमान हैं।

पसमांदा मुसलमानों की मिसाल

मोदी सरकार की आवास और राशन जैसी योजनाओं का फायदा भी पसमांदा मुसलमानों को मिल रहा है। देश के आम मुसलमान मोदी की इन योजनाओं का फायदा मिलने की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। और मौजूदा वक्त में मुसलमानों के बीच किस तरह का सेंटीमेंट है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक चिट्ठी सौंपी और इसमें लिखकर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उस दिन सबने मीट की दुकान बंद रखी।

और ये कोई अकेली मिसाल नहीं है। मुंबई से अयोध्या के लिए 1778 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर शबनम निकलीं। उनके कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर और जय श्रीराम का नारा लिखा हुआ बैनर साथ था। शबनम ने कहा था "मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूं जो रामजी को नेगेटिव वे में लेते हैं वे पॉजीटिव वे में लें, जन्मों के पाप धुल जाएंगे."

वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रहने वाली रूबी आसिफ खान ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर घर में राम दरबार की स्थापना की। देश में राम मंदिर को लेकर मुसमलानों के बीच भी किस तरह का सेंटीमेंट है इसकी कई मिसालें सामने आईं और मोदी की रणनीति से विपक्ष में हड़कंप मचा। विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी के राम मंदिर वाले दांव का जवाब कैसे दें।

मोदी ने कैसे बदली तस्वीर

ये नजीर इस बात की है कि कैसे कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी के बीच खलबली मची हुई है और कैसे राम के नाम पर राजनीति 360 डिग्री के एंगल पर घूमती हुई दिख रही है। वैसे मोदी की राजनीति पर सिर्फ विपक्ष की नजर नहीं है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त हिंदुस्तान पर है। 2024 के चुनाव नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की जा रही है। मोदी के सत्ता में आने के बाद तस्वीर कैसे और कितनी बदली है अब वो जानते हैं।

करीब 700 करोड़ की लागत से अबू धामी में बना ये पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है. अबू धाबी की जमीन पर बनकर तैयार हुआ ये वो मंदिर है जो 108 फीट ऊंचा है। 55 हजार वर्गमीटर में बन रहे इस मंदिर को भारतीय कारीगरों ने ही तराशा है। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के इस मंदिर के उद्घाटन किया।

पीएम मोदी यूएई का 2015 का दौरा

करीब 8 साल पहले मोदी का यूएई दौरा बेहद खास था क्योंकि पूरे 34 साल बाद यूएई किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा था. और अपने इसी ऐतिहासिक दौरे में ही पीएम मोदी ने तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच वहां की सरकार के सामने यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक हिन्दू मंदिर बनाने की पेशकश रख दी. नतीजा ये हुआ कि यूएई ने मंदिर के लिए हां कर दी.
साल 2018 में स्वामी नारायण मंदिर की आधारशिला पीएम मोदी के हाथों ही रखवाई गई थी और देखते ही देखते भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया. अब 14 फरवरी 2024 को पीएम मोदी इसी भव्य मंदिर का उद्घाटन करने अबू धाबी जाएंगे.

पीएम मोदी का यूएई का कार्यक्रम

13 फरवरी को पीएम मोदी यूएई पहुंचे। जहां कार्यक्रम का नाम अहलान मोदी रखा गया था। अहलान मोदी मतलब नमस्ते मोदी। इस कार्यक्रम को शेख जायद स्टेडियम में रखा गया। जहां अपार जनसमूह जुटा। इन से सीधा संवाद कर मोदी ने भारत का मान बढ़ाया। इसके बाद पीएम मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में बने भव्य मंदिर उद्घाटन किया। अबू धाबी में बना भव्य मंदिर इस बात पर मुहर लगाता है कि मोदी कैसे सनातन का सपना साकार कर रहे हैं।

विदेशी मीडिया में छाए मोदी

सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि 2024 में मोदी ही सत्ता में वापसी करेंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी ने उत्तरी बेल्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. जबकि ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि आगामी लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार जीतना लगभग तय है.
अमेरिका और ब्रिटेन के साथ-साथ चीन ने भी मोदी की खुलकर तारीफ की है. अब जरा इस बात को भी समझिए कि दुनिया के साथ-साथ मोदी देश के मुसलमानों का भरोसा कैसे जीत रहे हैं?

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे.. लक्षद्वीप वो केंद्र शासित प्रदेश है जहां 97 फीसदी आबादी मुसलमानों की है और मोदी ने यहां विकास की नई गंगा बहा दी. सिर्फ देश के मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने शादी शगुन योजना से लेकर उस्ताद योजना तक शुरू की है.

जिसमें शादी से पहले ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51 हजार की राशि शगुन के तौर पर दी जाती है और उस्ताद योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है. ईदी योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति' देने की स्कीम है.

मोदी मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं ये उन तक पहुंचाने और संवाद के लिए ही यूपी बीजेपी शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से 15 जनवरी से कार्यक्रम शुरू कर उनसे सीधा संपर्क साध चुकी है। जिससे साफ जाहिर है कि मोदी इस बार मुसलमानों को पूरा भरोसा जीतने की तरफ तेजी से बढ़ चुके हैं।

MBI
Direct From Factory

PARTNER WITH MADE BY INDIA

Expand & Accelerate Your Business's Growth

No Capital Investment required

Partner with the Market Leader

sales@madebyindia.com
07011412854
www.madebyindia.com

WEB Cadence INDIA

GET YOUR
DYNAMIC WEBSITE WITH CMS PANEL

Our Best Service

- 4-5 CUSTOM PAGES
- WHATSAPP CHAT INTEGRATION
- CONTACT FORM FOR LEAD GENERATION
- GOOGLE MAP INTEGRATION
- MOBILE FRIENDLY
- SEO FRIENDLY

+91 7982133887
www.webcadenceindia.com
asha@webcadenceindia.com

**TERMS & CONDITIONS APPLY

चुनावी चंदे का बही खाता

चंदावीरों' के चौंकाने वाले नाम

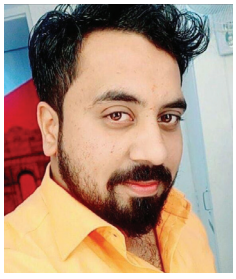

ऋषभकांत छाबड़ा
विशेष संवाददाता

चुनावी चंदे का शोर इन दोनों देश के हर कोई सुनाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SBI ने 13 मार्च को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी दी थी, जिसे 14 मार्च को चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, जिसे देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, आखिर ऐसा क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड में, जिसको लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ है. वो आज इस वीडियो में एक-एक बात आपको आसान भाषा में समझाते है ताकि आप भी जान सके की टाटा, अंबानी, या अडानी नहीं बल्कि इनसे भी ज्यादा कई उद्योगपतियों ने राजनीतिक दलों को करोड़ों, अरबों में चुनावी चंदा दिया है.

सबसे पहले ये जानते है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है दरअसल राजनीतिक दलों को चंदा देने का ये एक वित्तीय ज़रिया है. ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी SBI की चुनिंदा शाखाओं से ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीक़े से दान कर सकता है. मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी. इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को क़ानूनन लागू कर दिया था. जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है. राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया लेकिन कोई सॉलिड जवाब सरकार की ओर से नहीं मिल सका.

हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो SBI को कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन लोगों ने राजनीतिक चंदा दिया है उसको पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को दें, ताकि वो जल्द से जल्द सार्वजनिक करें, जैसे ही SBI ने बंद लिफाफे में पेनड्राइव के जरिए दो पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल्स चुनाव आयोग को दी. जिसमें एक फाइल में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है. जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए उसकी विस्तृत जानकारी है. ये जानकारी 12 अप्रैल, 2019 से 11 जनवरी, 2024 के बीच की है. बता दें जैसे ही जानकारी पब्लिश हुई सियासी हड़कंप मच गया, कांग्रेस ने इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया. ऐसे में पहले ये जानते है किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला फिर उसके बताएंगे किस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है. EC की ओर से जारी चुनावी बॉन्ड इनकैश करवाने वालों की लिस्ट में चंदा लेने में अव्वल राजनीतिक दल?

BJP पहले नंबर पर है जिसे **6060** करोड़ रुपये

TMC **1609**

कांग्रेस **1421**

BRS **1214**

बीजद **775**

DMK **639**

YSR कांग्रेस **337**

तेलुगु देशम पार्टी **218**

शिवसेना **158**

राजद **72.50**

ये तो हो गई राजनीतिक दलों की बात लेकिन अब जानते है किस कंपनी ने कितने रुपये दिए है.

किस डोनर ने दिया कितना डोनेशन?

फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज **1,368 करोड़**	मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड **966 करोड़**	क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड **410 करोड़**
वेदांता लिमिटेड **400 करोड़**	हल्दिया एनर्जी लिमिटेड **377 करोड़**	भारती ग्रुप **247 करोड़**
एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड **224 करोड़**	वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन **220 करोड़**	केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लिमिटेड **194 करोड़**
मदनलाल लिमिटेड **185 करोड़**	डीएलएफ ग्रुप **170 करोड़**	यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल **162 करोड़**
उत्कल एलुमिना इंटरनेशनल **145.3 करोड़**	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड **123 करोड़**	बिड़ला कार्बन इंडिया **105 करोड़**

इस लिस्ट में और भी नाम है लेकिन 15 ये नाम ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों को चंदा दिया है. गौर करने वाली बात है इन नामों में देश के बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप का नाम नहीं है. साथ ही टाटा ग्रुप और सीधे तौर पर अंबानी ग्रुप का भी नाम नहीं है. बता दें SBI ने 2018 में शुरू हुई योजना के बाद से अब तक 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक की है. हलफनामे में बताया गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, जो कि इस तीन मूल्यवर्ग यानी ₹1 लाख, ₹10 लाख और ₹1 करोड़ के हैं. इस अवधि के दौरान भुनाए गए बॉन्ड की संख्या 22,030 है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें इन कैश कराने वालों के तो नाम हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किसने ये पैसा किस पार्टी को दिया?

इस मामले में याचिका लगाने वाले ADR के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि SBI ने वो यूनिक कोड नहीं बताया, जिससे पता चलता कि किसने-किसे चंदा दिया.

कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने कहा, दानदाताओं और इसे लेने वालों के आंकड़े में अंतर है. दानदाताओं में 18,871 एंट्री है, जबकि लेने वालों में 20,421 की एंट्री है. पार्टी ने ये भी पूछा है कि ये योजना 2017 में शुरू हुई थी तो इसमें अप्रैल 2019 से ही डाटा क्यों है?

आयोग का कहना है कि उसे ये जानकारी SBI से ऐसी ही मिली है. 2019 से 2024 के बीच 1334 कंपनियों-लोगों ने कुल 16,518 करोड़ रु. के बॉन्ड खरीदे. 27 दलों ने भुनाए.

हालांकि इस मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. जहां सुप्रीम कोर्ट ने SBI से पूछा कि आपने बॉन्ड नंबर डिस्कलोज क्यों नहीं किया. हमने अपने ऑर्डर में सब डिटेल देने को कहा था. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने SBI को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा कि नंबर डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया.

हालांकि इन सबके बीच टॉप पर जो दो कंपनियां है उसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं. जिनके बारे में भी जानते है. रिपोर्ट्स की मानें तो लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने सबसे ज्यादा 1368 करोड़ का चंदा दिया है.

मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे हैं. मार्टिन की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत कई केस दर्ज हैं.

2019 से 2024 के बीच 1334 कंपनियों-लोगों ने कुल 16,518 करोड़ रु. के बॉन्ड खरीदे

फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था. ये कंपनी सिक्किम, नगालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है. फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स सर्विसेज के खिलाफ ED ने 23 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की थी.

वहीं दूसरा नाम आता है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का जिसने 966 करोड़ रुपये चंदा दिया है. इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कंपनी ने 2019 और 2024 के बीच 1000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं. कृष्णा रेड्डी इस कंपनी को चलाते है. इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार की कालेश्वरम डैम परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है. ये जोजिला सुरंग और पोलावरम डैम को भी बना रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर 2019 में आयकर विभाग ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. इसके बाद ईडी की ओर से भी जांच शुरू की गई. उसी साल 12 अप्रैल को MEIL ने 50 करोड़ रुपये के बांड खरीदे थे. पिछले साल, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD और उसके हैदराबाद स्थित भागीदार MEIL के 1 बिलियन डॉलर के निवेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया था.

हालांकि इन दोनों के अलावा, कई कंपनियां ऐसी भी है जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे है. जिसमें सबसे पहला नाम आता है, अदार पूनावाला का. जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ है. कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बना कर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफी पैसा भी बनाया. वैक्सीन बनाने के अगले ही साल, यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी. 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए. 15 दिन बाद और ढाई करोड़ रुपए दिए. प्रूडेंट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए की ये कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी. इससे पता चलता है कि कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी थी, वहां कॉरपोरेट घरानों से मिलने वाले चंदों से बीजेपी का खजाना भर रहा था. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं. अब आगे अगली सुनवाई में SBI क्या कुछ कोर्ट में बताता है ये देखने वाली बात होगी.

डॉ. ए.के. सिंह
प्रोफ़ेसर,
पतंजलि विश्वविद्यालय,
हरिद्वार, उत्तराखंड

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 उत्तर प्रदेश मे इसकी यथार्थतता

भारतीय संसद ने 01 मई 2016 में रेरा कानून तथा 18 मई 2016 को आईबीसी कानून बनाया। रेरा के बारे में पिछले दो अंकों में एक विस्तृत जानकारी साझा की। यहां यह बताना आवश्यक है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से रेरा कानून बनाकर खरीदारों को बिल्डरों से होने वाले लूट पर रोक लगाने का एक प्रयास था उसी के समकक्ष आईबीसी कानून बनाकर उन्ही बिल्डरों को एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करने का भी हथियार भी इसी सरकार ने दे दिया।

यह कानून क्या कहता है इसकी एक संक्षिप्त जानकारी हम इस लेख के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) एक समेकित कानून है जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए दिवाला और दिवालियापन कार्यवाही को नियंत्रित करता है। 18 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई। आईबीसी से पहले, दिवालियापन और पुनर्गठन के लिए विधायी ढांचा कई कानूनों में विभाजित था, जैसे कंपनी अधिनियम 2013, बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, वित्तीय संपत्तियां का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम 1993 इत्यादि लागू थे। इन सभी कानून को हटाकर दीवाला तथा दिवालियापन संहिता 2016 को लाया गया। ज्ञातव्य हो कि बिल्डर भी कंपनी नियम के दायरे में आते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए बिल्डरों ने आईबीसी कानून का भरपूर दुरुपयोग कर डाला।

सरकार द्वारा उपर्युक्त सभी कानून को हटाकर एक कानून बनाने की मंशा से इस कानून को संसद में पास किया गया। आईबीसी की परिकल्पना है कि संपूर्ण कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आवेदन स्वीकार होने के 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए। सीआईआरपी को किसी भी विस्तार या मुकदमेबाजी अवधि सहित, 330 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। यह कानून कितना प्रभावी है इस बात से समझा जा सकता है कि जिस प्रक्रिया को 330 दिन में पूरी कर लेनी चाहिए वे 5 साल से एनसीएलटी कोर्ट के समक्ष लंबित है।

कानून बनाते समय कानून इतना लचीला बना कि इसकी धाराओ का दुरुपयोग करते हुए कंपनियों ने इसे अपनी सुरक्षा कवच बना डाला। जिसका नतीजा यह रहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डरों के प्रोजेक्ट में से 133 प्रोजेक्ट इसी दिवालिया प्रक्रिया संहिता का उपयोग कर एनसीएलटी में लंबित है। ऐसे सभी बिल्डर हजारों निवेशकों सैकड़ो करोड रुपए की गाढ़ी कमाई लूटकर फरार होने की जुगत में है। यही नहीं एनसीएलटी द्वारा बनाए गए आईआरपी बिल्डरों के साथ मिलकर बड़ा खेल कर रहे हैं। और एक ऐसा नया गठजोड़ तैयार हो गया कि अब खरीदारों को इस गठजोड़ से भी लड़ना पड़ेगा जिसमें एनसीएलटी, आईआरपी, बिल्डर, रेरा व जिला प्रशासन है। खरीदार केवल घूम रहा है। हजारों खरीदारों के आरसी वसूली इसलिए नहीं हो पा रही है की को आईबीसी कानून का दुरुपयोग कर बिल्डर एनसीएलटी में चले गए।

इस तरह से बिल्डरों ने रेरा के आदेशों की धज्जियां उड़ा रखी है। रेरा इतनी असहाय है कि अपने ही आदेश को पालन करने के स्थिति में नहीं है। बिल्डर रेरा के आदेशों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते ना ही उनके आदेशों पर कोई कार्रवाई की मंशा रखते हैं। इस तरह से रेरा भी बिल्डरों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर रहा है। खरीदार रेरा मे आता तो है समाधान के लिए लेकिन एक और समस्या लेकर के चला जाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो उसका बिल्डर सुनता है और ना ही रेरा। रेरा यह कर कह करके हाथ खड़ा कर देता है कि जो केस एनसीआरटी में चले गए हैं उन बिल्डरों पर रेरा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। खरीदार इस असमंजस में है कि हम कहां जाएं रेरा के आदेश का कोई पालन नहीं करता फिर हाई कोर्ट जाएं वहां से समाधान नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट जाए। कोर्ट कोर्ट के इस खेल में कितने लोग अपनी जिंदगियां गवा चुके हैं और आगे आने वाले कितने लोगों को गंवाना पड़ सकता है। इसका सरकार कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं लगा पाया।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पहला फुट ओवर ब्रिज, सांसद बोले- यहां के लोगों के सभी सपने होंगे पूरे

वैसे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट वासियों की तमाम समस्याएं हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ता दिख सकता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वालों की प्रमुख समस्याओं में अधूरे पड़े बिल्डर के प्रोजेक्ट, रजिस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट (मेट्रो की मांग) शामिल है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आबादी लाखों में है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होने के चलते चार मूर्ति से एक मूर्ति तक लंबे जाम की स्थिति बनी रहती है। यहां के लोग लंबे समय से फुट ओवर ब्रिज की मांग कर रहे थे, जो अब पूरा होता दिख रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पहला फुट ओवर ब्रिज अब आम जनता के खुल चुका है, ये फुट ओवर ब्रिज एक मूर्ति चौराहे पर बना है। करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से तैयार हुए एफओबी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पैदल सड़क पार करने के चक्कर में यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती थी, जिस पर अब लगाम लगने की पूरी उम्मीद है।

> ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस फुट ओवर ब्रिज से आम जनता को बड़ी राहत मिली है
>
> **महेश शर्मा, सांसद, गौतमबुद्ध नगर**

> ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विकास को कोई रोक नहीं सकता। यहां के निवासियों के सभी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा
>
> **तेजपाल नगर, विधायक, बीजेपी**

पूजा मिश्रा
उपसंपादक़

दक्षिण का दुर्ग जीतने का मोदी प्लैन

अबकी बार, 400 पार। ये NDA का टारगेट है। BJP का टारगेट 370 प्लस सीट का है। मोदी की हर रैली में यही नारा गूंज रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है। क्या है BJP का प्लैन। इस प्लानिंग के कई पहलू हैं। पहला, जिताऊ कैंडिडेट को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। बीजेपी की लिस्ट में भी 100 से अधिक सांसदों का टिकट कटने की अटकलें लगाई गईं। दूसरा, जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, उन पर करिश्माई कैंडिडेट उतारने का प्लैन बना। लिस्ट में कंगना रानौत युवराज सिंह और अक्षय कुमार जैसे स्टार के नाम पर भी चर्चा हुई। तीसरा, गठबंधन के सहयोगियों के साथ जीत की गारंटी वाली सीट ली जाए। चौथा, जिन सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट नहीं हैं, उसकी भरपाई दूसरे दलों से आने वाले टिकाऊ नेता को टिकट दिया जाए। बीजेपी चौथा फॉर्मूला दक्षिण भारतीय राज्यों में आजमा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में दक्षिण भारतीय राज्यों से 55-60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तमिलनाडु और तेलंगाना में पार्टी अपने चौथे फॉर्मूले को आजमा रही है।

30 नई सीटें जीतने की चुनौती

दक्षिण भारत में 132 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली थीं। कर्नाटक में बीजेपी को 25 और तेलंगाना में चार सीटें मिली थीं। तमिलनाडु,आंध्रप्रदेश, केरल, पुडुचेरी में पार्टी का खाता नहीं खुला था। पिछले आम चुनाव में भाजपा का निजी स्कोर 303 रहा था। 370 के आंकड़े को हासिल करने के लिए पार्टी के लिए दक्षिण भारत के पांच राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेश में लंबी छलांग लगानी होगी। दक्षिण भारत में पार्टी ने दक्षिण में 84 सीटों को चिह्नित किया है, जहां बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है। खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगले चुनाव में पार्टी को कर्नाटक की 25 सीटों के अलावा 30 नई सीटें जीतनी होंगी। बीजेपी ने इस विस्तार के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को वरीयता में रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जनवरी और फरवरी के बीच दक्षिण भारत में 11 दिन गुजारे हैं। इन दौरों में उन्होंने केंद्र की परियोजनाओं

के साथ जनसभाएं कीं। अभी चुनावी सभाओं का दौर बाकी है, जो मार्च के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा।

तमिलनाडु में त्रिकोण प्लान

तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और 15 सीटें बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी की रैली और के. अन्नामलाई की यात्रा के बाद इनमें से सात सीटों शिवगंगा, रामनाथपुरम, थेनी, मदुरै, विधुनगर, थूथुकूडी और कन्याकुमारी पर पार्टी का परचम बुलंद हो सकता है। इसके अलावा पार्टी नीलगिरी (एससी), दक्षिण चेन्नई, कोयंबटूर, तेनकासी,तिरुनेलवेली, उत्तरी तमिलनाडु में वेल्लोर, विल्लुपुरम और कल्लाकुरिची पर भी फोकस कर रही है। गठबंधन तोड़ने के बाद तमिलनाडु में बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के नेताओं पर नजर टिका दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तिरुपुर यात्रा में एआईडीएमके नेता जयललिता और एम जी रामचंद्रन को अतुलनीय नेता बताकर इस ओर इशारा भी कर दिया। सूत्रों के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य ईकाई को ऐसी पार्टियों से चुनावी गठबंधन करने का मंत्र दिया है, जो 2014 और 2019 के चुनावों में क्षेत्रीय जनाधार के बाद भी जीत हासिल नहीं कर सके। तमिल मनीला कांग्रेस से गठबंधन कर इस अभियान की शुरूआत की जा चुकी है। संभावना है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक पाताली मक्कल काची (पीएमके), अभिनेता विजयकांत की देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके), टीटीवी दिनाकरण की अध्यक्षता वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) से समझौता हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो एआईडीएमके तमिलनाडु में अकेली हो जाएगी और राज्य में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। इसके अलावा एआईएडीएमके से निकाले नेता ओ पन्नीरसेल्वम को भी बीजेपी में शामिल करने की संभावना प्रबल है।

विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची है। पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले तीन बीआरएस सांसदों ने बीजेपी जॉइन कर ली

तेलंगाना में पावर डबल

तेलंगाना में बीजेपी ने दहाई अंक में सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 19.65 फीसदी वोट और चार लोकसभा सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को 13.90 फीसदी वोट मिले, हालांकि सीटें कम मिलीं। वोटों के गैप को खत्म करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के बजाय बीआरएस के वोट बैंक और नेताओं को लुभाना शुरू किया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीआरएस में भगदड़ मची है। पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के ऐलान से पहले तीन बीआरएस सांसदों ने बीजेपी जॉइन कर ली। इन नेताओं में जहीराबाद से दो बार के सांसद बीबी पाटिल और नगरकुर्नूल

के बीआरएस सांसद पोथुगंती रामुलु जैसे दिग्गज शामिल हैं। लिंगायत नेता बीबी पाटिल का असर तेलंगाना के साथ कर्नाटक में नजर आएगा। बीजेपी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी निजामाबाद से अरविंद धर्मपुरी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी और करीमनगर से बंदी संजय पर दोबारा दांव लगाएगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय का एकमुश्त वोट मिला था। अब पार्टी ने हिंदूवादी नेता टी एस राजा सिंह को लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है।

आंध्र में सितारों की आंधी

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का आंध्रप्रदेश में खाता नहीं खुला था। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी टीडीपी और जनसेना से पांच सीटों की मांग की है। टीडीपी सिर्फ चार सीट देने को सहमत है। आंध्र प्रदेश की 17 लोकसभा सीट में से 3 पहले ही जनसेना को दे चुकी है। बीजेपी के हिस्से में तिरुपति, राजमपेट, अराकू और राजमुंदरी सीट आ सकती है। बीजेपी गठबंधन से विशाखापटनम भी मांग रही है, जिस पर टीडीपी सहमत नहीं है। पीएम मोदी ने हाल ही में यह दावा किया है कि इस बार बीजेपी केरल में डबल डिजिट में सीटें जीतेगी। मगर सूत्र बताते हैं कि पार्टी का फोकस सिर्फ चार सीटों तिरुवंतपुरम, पथटमथिट्टा, त्रिशूर और अटिंगल तक सिमटा है और खुद पार्टी दो सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को केरल में एक सीट भी नहीं मिली है। 55 फीसदी हिंदू वाले केरल में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 13 फीसदी वोट मिले थे। कांग्रेस सांसद भी शशि थरूर भी पीएम मोदी के दावे से सहमत नहीं हैं। उनका दावा है कि बीजेपी का फिर केरल में खाता नहीं खुलेगा। हालांकि भगवा पार्टी तमाम दावों से उलट 24 में चमत्कार की उम्मीद पर कायम है। तो इसके पीछे सिर्फ एक चेहरे की ताकत है। वो चेहरा है नरेंद्र मोदी।

आंध्र प्रदेश की 17 लोकसभा सीट में से 3 पहले ही जनसेना को दे चुकी है। बीजेपी के हिस्से में तिरुपति, राजमपेट, अराकू और राजमुंदरी सीट आ सकती है।

अजय पाल नागर
लेखक एवं शिक्षाविद

भौतिकवाद में रिश्तों का पतन

वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात सम्पूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने वाला भारत, विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो)दुनिया के लोगों को भाई बहन कहकर सम्बोधित करने वाले स्वामी विवेकानंद का भारत, आज रिश्तों की गिरावट में किस स्तर तक आ पहुंचा है ! जो कि चिंता और चिंतन का विषय है।

भारत जब विदेशी ताकतों के अधीन था और आजाद होने के बाद भी गरीबी ,भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी का बोलबाला था। ग्रामीण भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। लोगों के पास तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं थे, लोग एक ही कपडे से महीनों-महीनों निकाल देते थे। यहाँ तक कि शादी या अन्य किसी कार्यक्रम में हर किसी के पास नये कपडे तक नहीं होते थे, कई बार तो लोग एक -दूसरे से कपडे जूते उधार मांग कर शादी या अन्य कार्यक्रमों में जाते थे और कार्यक्रम के उपरांत वापस कर देते थे। शाम के समय मोहल्ले में किसी एक के घेर (जहाँ केवल पुरुष रहते थे) पर बैठकर सभी अपने सुख -दुख की चर्चा करते थे। किसी पर दुख या मुसीबत आने पर सभी मिलकर एक -दूसरे की मदद करते थे।

उस समय मकान बेशक कच्चे थे, लेकिन दिल सभी के सच्चे थे,
आज मकान सभी के प हैं , पर दिल सभी के कच्चे हैं।

उस समय न तो पैसा कमाने की दौड़ थी न भौतिक वाद की चमक थी, मशीनीकरण भी नहीं हुआ था, खेती करने के लिए ट्रैक्टर भी गाँव में किसी एक -दो के पास हुआ करता था। गांवों में अधिकतर बेलों से खेती होती थी और यदि किसी के पास एक ही बेल होता था तो वह किसी अन्य के साथ मिलकर (डंगवारा करके) अपनी खेती करता था। इस प्रकार दोनों का काम हो जाता था। फसल कटाई भी एक -दूसरे से मिलकर कर लेते थे। यहाँ तक कि भूसा का बांगा बांधने के लिए मजदूर नहीं लेने पडते थे सभी लोग मिलकर एक दूसरे का कार्य करते थे। आपस में भाई चारा हुआ करता था। घर मे एक भाई का कहना सभी लोग आदेश के रूप मे मानते थे। पूरे गांव में एक दो लोग ही मुख्य हुआ करते थे जो चुनाव से लेकर आपसी विवादों तक का निपटारा गांव में ही करा देते थे। पुलिस और अदालत तक तो बहुत ही कम मामले पहुचते थे।

उस समय डायबिटीज, ब्लड प्रेशर , माईग्रेन जैसी बीमारियों के विषय में किसी को पता तक नहीं था। सभी लोग गरीबी में सगे सम्बंधियों के साथ संयुक्त परिवार में बिना किसी भागदौड़ के आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे।

आज हम तरक्की के नये-नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। आसमान से लेकर समुंद्र तक, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक, हमनें अनेकों मील के पत्थर स्थापित किये हैं। लेकिन इस तरक्की में हमने काफी कुछ रिश्ते- नाते, गांव-गलियारे, खेत -खलिहान , गांव की चौपाल , मां का प्यार और पिता की फटकार बहुत कुछ गंवाया है।

आज हम गांव के बडे -बडे घरों को छोड़कर शहर के छोटे-छोटे फ्लैटों में आ गये हैं जहाँ साथ रहते हुए भी कोई साथ नहीं है और माता -पिता के लिए भी इनमें कोई जगह नहीं है। हां ! विदेशी नस्ल के कुत्ते जरूर इनकी शोभा बढा रहे हैं। कोई एक दूसरे को पहचान कर भी यहाँ पहचानता नहीं है। सब एक -दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हैं और इस दौड का कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा है, केवल दौडे जा रहे हैं। बताने में फक्र महसूस होता है कि मैं फलां पाश सेक्टर की फलां सोसायटी में रहता हूँ। वहाँ मेरी पहचान मेरे फ्लैट के नम्बर से है जबकि गांव में मुझे लोग मेरे पिताजी, दादा जी ,परदादा के नाम से पहचानते हैं यही मेरी तरक्की है।

शिक्षा में हमने इतनी तरक्की की है कि बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए इतना दबाव रहता है कि राजस्थान के कोटा में बच्चे दबाव में आकर आत्म हत्या तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर में किसी अपने की मौत पर शोक मनाने के बजाय बच्चों की परीक्षा की चिंता है, उनकी तरक्की की चिंता है। परीक्षा में नम्बरों के प्रतिशत की चिंता है बस केवल रिश्तों की चिंता नहीं है। आगे चलकर यह बच्चों की तरक्की की चिंता शहरों में वृद्धआश्रमों के प्रतिशत की संख्या में वृद्धि के साथ ही वृद्धों की आश्रमों में प्रतिशत की संख्या वृद्धि का कारण भी बन रहा है। आज भी किसी गांव में कोई वृद्ध आश्रम नहीं है।

बेशक अब गांव में चौपाल नहीं लगती, अब कोई बेमतलब किसी के पास नहीं जाता, पहले पूरे गाँव का एक मुखिया हुआ करता था, आज हर घर मे कई-कई मुखिया हैं। आज हर रिश्ता तरक्की की राह खोजता है, पर रिश्ते की तरक्की की राह कोई नहीं खोजता। पहले एक व्यक्ति की बात घर के सभी लोग मानते थे, आज घर के सभी लोग आपस में बात तक नहीं कर पाते। वैसे भी अब सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान जो हो गया है। आज रिश्तों पर पैसा भारी पड रहा है, संपत्ति के लिए भाई-भाई का कत्ल कर रहा है। नैतिकता अब मृतप्राय हो चुकी है। क्या बच्चे ! क्या बड़े ! सभी तरक्की की मैराथन में दौड़ रहे हैं। आज भौतिकवाद की आग में रिश्ते जलकर राख हो गये हैं।

आदर्श आचार संहिता?

देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनावों की तारीखों के साथ ही देश में आचार संहिता लागू है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सात चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। आयोग के अनुसार ये प्रक्रिया 6 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। चुनाव आयोग जैसे ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, वैसे ही मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। इनमें दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने तक की कार्रवाई शामिल है, ज़रूरी होने पर आयोग आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है, यहां तक कि दोषी पाए जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है।

1. आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, योजनाओं की घोषणा, परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं किया जा सकता।
2. सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है।
3. किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी।
4. कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता न ही वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकता है जिससे धर्म या जाति के आधार पर मतभेद या तनाव पैदा हो।
5. राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए।
6. अनुमति के बिना किसी की ज़मीन, घर, परिसर की दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर आदि नहीं लगाए जा सकते।
7. मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं. वोटरों को शराब या पैसे बाँटने पर भी मनाही होती है।
8. मतदान के दौरान ये सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के शिविर में भीड़ इकट्ठा न हों।
9. शिविर साधारण हों और वहां किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद न हो, कोई भी खाद्य सामग्री नहीं परोसी जाए।
10. सभी दल और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें जो चुनावी आचार संहिता के तहत 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध की श्रेणी में आते हैं- जैसे मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, फ़र्ज़ी वोट डलवाना,
11. मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
12. राजनीतिक कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक या ऑब्ज़रवर नियुक्त करता है।
13. आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाज़त के बिना किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता है।

यमुना प्राधिकरण ने पास किया लगभग 100 अरब का बजट

एयरपोर्ट, रैपिड रेल और एक्सप्रेसवे पर बढ़ाया खर्च

चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 80वीं बोर्ड बैठक मार्च महीने की 12 तारीख को संपन्न हुई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राधिकरण ने 9,992.20 करोड़ रूपये का बजट सामने रखा, जो यमुना अथॉरिटी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट विकास के लिए पास किया है। इसमें प्राधिकरण 9,579 करोड़ रूपये भूमि अधिग्रहण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे खर्च करेगा।

भूमि अधिग्रहण पर सबसे ज्यादा खर्च

इसी महीने से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष लिए 12 मार्च को बजट यमुना प्राधिकरण ने पेश किया जिसे बोर्ड ने मंजूरी दी। नए वित्त वर्ष के लिए 9992.20 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें भूमि आवंटन पर 6 हजार करोड़ रूपये से अधिक प्राधिकरण खर्च करेगा, जो पिछले साल की अपेक्षा 100 फीसदी अधिक है। ये पूरे बजट का 80 फीसदी से भी ज्यादा है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान 2031 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। गौतमबुद्ध नगर से आगे बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में भूमि अधिग्रहण होगा। वहां विभिन्न आवासीय और औद्योगिक विकास योजनाएं अगले साल के दौरान मूर्त रूप लेंगी।

जेवर एयरपोर्ट पर 702 करोड़

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के जेवर इलाके में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका पहला फेज पूरा होने वाला है। जल्दी दूसरे फेज पर काम शुरू होगा। हवाईअड्डा परियोजना में यमुना प्राधिकरण 17.5 प्रतिशत का हिस्सेदार है। इस बजट में जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान यमुना प्राधिकरण जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 702 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

ये हैं प्राधिकरण की महत्वकांक्षी योजनाएं

इस साल के बजट में यमुना प्राधिकरण ने कई महत्वकांक्षी योजना तैयार की है। इसमें नए अलॉटमेंट, नए सेक्टर्स जिसमें सेमीकंडक्टर, डाटा पार्क, एमसीटू की भारत सरकार की पीएलआई स्कीम, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स को शामिल किए गये हैं। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 8 नए सेक्टर्स के लिए जमीनें भी खरीदी जानी हैं। यमुना प्राधिकरण नए सेक्टर्स के लिए भूमि अधिग्रहण करने जा रही है। इन सेक्टर्स में नए क्लस्टर्स का विकास किया जाएगा। इसमें ईवी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, हैंडीक्रॉफ्ट और हैंडलूम पार्क के लिए नए क्लस्टर्स तैयार किये जाने हैं।

जानें कितनी कमाई की संभावना

सीईओ ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान विकास प्राधिकरण 9,992.24 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्त करने की संभावना है। इनमें भूमि आवंटन के जरिए 7,635 करोड़ रूपये की आय होगी। यह पिछले वित्त वर्ष के मुक़ाबले 102 प्रतिशत ज़्यादा रहने का अनुमान है। लीज़ रेंट और दूसरे शुल्कों के माध्यम से 706 करोड़ रूपये की आय की आय होने की संभावना है। इस मद में पिछले वित्त वर्ष के मुक़ाबले 222% ज़्यादा आय होने का अनुमान है। विकास योजनाओं को रफ़्तार देने के लिए प्राधिकरण एडवांस और लोन लेगा। सीईओ ने बताया 1,650 करोड़ रुपये अग्रिम और ऋण लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस तरह अगले वित्त वर्ष के दौरान 9,992.24 करोड़ रूपये अथॉरिटी अर्जित करेगी।

व्यक्तिगत चुनाव कैसे?

गौतमबुद्ध नगर की लोकसभा की सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से जहां भाजपा ने डॉ. महेश शर्मा को हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं, सपा ने दो बार उम्मीदवार बदलते हुए महेंद्र नागर पर दांव खेला है। जबकि गौतमबुद्ध नगर सीट अस्तित्व में आने के पहला चुनाव जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी ने पुराने कार्यकर्ता राजेंद्र सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां पर जैसे ही बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी के नाम का ऐलान किया तो यहां का समीकरण पूरी तरह से बदल गया। बसपा उम्मीदवार राजेंद्र सोलंकी ने Now Noida के संदीप ओझा से चुनावी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की।

राजेंद्र सोलंकी ने खास बातचीत में कहा कि इस चुनाव में उनकी सीधी टक्कर भाजपा उम्मीदवार महेश शर्मा से है। राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि 'इस सीट पर उनकी चुनौती कोई नहीं है. लेकिन उनका चुनाव महेश शर्मा से होगा, क्योंकि महेश शर्मा ने यह चुनाव व्यक्तिगत बना दिया है. ऐसे में बसपा सुप्रिमो ने मुझपर भरोसा जताया है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चुनाव में मैं ही विजय हूं'.

"महेश शर्मा ने चुनाव को बनाया पर्सनल"

Now Noida से बातचीत में राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव इसलिए व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि मैं सभी को साथ लेकर चल रहा हूं. आज मेरे साथ पूरा समाज है. हर जाति और धर्म के लोग है. लेकिन महेश शर्मा कुछ चंद लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. व्यक्तिगत चुनाव होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जगह-जगह मेरा नाम लेते हैं. मेरे बारे में गलत बताते हैं. जबकि मैं उनका नाम कही नहीं लेता हूं.

"ठाकुर समाज के लिए महेश शर्मा पूज्यनीय नहीं"

वहीं, ठाकुर समाज बीजेपी का वोट बैंक है। इस सवाल के जवाब में कहा कि ठाकुर समाज बीजेपी का समर्थक माना जाता है। इसकी जानकारी तो नहीं है. लेकिन हां ठाकुर समाज सबसे ज्यादा गणेश और गौतमबुद्ध की पूजा करता है और उसके लिए महेश शर्मा पूज्यनीय नहीं है। बल्कि पार्टी किसी के लिए पूज्यनीय नहीं है. लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर साफ पता चलता है कि आज वहीं, उनसे कटता जा रहा है।

"बसपा के बाद किसी भी पार्टी ने नहीं किया विकास"

वहीं, सांसद बनने के सवाल पर राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर में विकास बसपा के समय में हुआ है. यहां जितने ही स्कूल और कॉलेज हैं, सब बहन मायावती की ही देन है. जब से गौतमबुद्ध नगर में सत्ता बदली तो कुछ विकास नहीं हुआ। अगर मुझे जनता का आशिर्वाद मिलता है तो मैं सबसे पहले रुका हुआ विकास को पूरा करूंगा.

"विकास करने वालों का करें सम्मान"

राजेंद्र सोलंकी ने बिल्डर बायर मामले में पर कि जो विकास करें, उसका हमें हमेशा समर्थन और सम्मान करना चाहिए और जो विकास ना करें उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेट्रो से लेकर सभी विकास के काम बसपा ने किए है. इसके बाद से यहां किसी भी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया. चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी.

समस्याओं से कैसे निपटेंगे डॉ. महेश शर्मा

देश में 18वें लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार जहां बीजेपी ने अपने सैकड़ों वर्तमान लोकसभा सांसदों के टिकट दिए तो वहीं गौतमबुद्ध नगर से बीजेपी के वर्तमान सांसद डॉ. महेश शर्मा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। डॉ. महेश शर्मा को राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। लगातार चौथी बार आम चुनाव में गौतमबुद्ध नगर से बीजेपी की दावेदावी पेश करने जा रहे डॉ. महेश शर्मा कितने मजबूत हैं इस बार के चुनाव में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हालिए माहौल तो उनके फेवर में दिख रहा है। गौतमबुद्ध नगर सीट से साल 2014 में दूसरी बार बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे डॉ. महेश शर्मा पहली बार सांसद बने थे। उसके बाद साल 2019 में भी भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद इस बार साल 2024 में भी पार्टी ने डॉक्टर साहब पर ही दांव खेला है। डॉ. महेश शर्मा से Now Noida अपडेट के संपादक संदीप ओझा ने डॉ. महेश शर्मा से बातचीत की। पेश है बातचीत के अंक।

संदीप ओझा- डॉक्टर साहब इस बार लोकसभा चुनाव में आपके सामने सपा के डॉ. महेंद्र नागर और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं, दोनों ही प्रत्याशियों का कहना है कि उनकी लड़ाई सीधे आप से है, आपके लिए दोनों में से कौन चुनौती बनने वाला है?

डॉ. महेश शर्मा- क्या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती हैं। हम तो बीजेपी के सिपाही हैं, ये चुनाव में तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व का लोगों के बीच में इतना बड़ा कद है तो चुनौती का सवाल ही नहीं पैदा होता। रही बात दोनों प्रत्याशियों की तो पिछले चुनाव का इतिहास देख लें एक पार्टी तो पूरी तरह से खत्म है, उनके एक भी प्रत्याशी पिछले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं सके थे और दूसरी पार्टी है उनके कुल मिलाकर तीन सांसद हैं। तो हम इनमें से दोनों किसी पार्टी को चुनौती नहीं मानते। रही बात लोकसभा चुनाव की तो केवल गौतमबुद्ध नगर जिले अकेले में ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश है बीजेपी मय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम और काम इतना बड़ा है कि दूसरी कोई पार्टी उनके सामने है ही नहीं।

संदीप ओझा- डॉक्टर साहब जिन लोगों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का श्रेय जाता है, उसमें आप का भी नाम शामिल है लेकिन जेवर के पास ही कई ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण इस बार चुनाव बहिष्कार की बात कह रहे हैं। उनमें क्या ऐसी नाराजगी है?

डॉ. महेश शर्मा- उनकी समस्याएं विस्थापन को लेकर है, मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं उनकी जो भी समस्याएं होंगी, मैं खुद उनके बीच जाकर बात करूंगा और उन्हें समझाउंगा। क्योंकि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें मैं दूर करवाउंगा। चुनाव का बहिष्कार कोई भी नहीं करेगा। विस्थापन को लेकर जो भी समस्याएं हैं, उन्हें साथ बैठकर दूर करवाया जाएगा।

संदीप ओझा- ग्रेटर नोएडा वेस्ट की समस्याएं क्या आपके लिए चुनौती बनेंगी, क्योंकि वहां पर बिल्डर-बॉयर्स की समस्या और पबल्कि ट्रांसपोर्ट की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहां के लोग इसे लेकर खासे नाराज हैं, आपने अभी तक इसका निस्तारण क्यों नहीं करवाया।

डॉ. महेश शर्मा- बिल्डर-बायर्स की समस्या पिछली सरकारों की देन है, कौड़ियों के भाव यानि केवल 10 प्रतिशत लेकर जमीन बिल्डर्स को सौंप दी गई। आज हालत है कि आम लोगों को ठगने वाले बिल्डर जेल में हैं और जो बिल्डर सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे बचे पैसे लेकर रजिस्ट्री भी करवाई जा रही है। इस सरकार ने आम लोगों की सहुलियत के रेरा का गठन किया, अमिताभ कांत समिति बनाई जिनकी सिफारिशों पर रजिस्ट्री का काम तेजी से चल रहा है। रही बात मेट्रो की तो केंद्रीय मंत्री हरीदीप पुरी जी से मीटिंग हो चुकी है, डीपीआर भी अप्रूव हो चुका है। यहां तक कि यूपी ने अपने हिस्से का 50 फीसदी पेमेंट भी जारी कर दिया है। इस पर अब आपको चुनाव के बाद तेजी से काम दिखेगा।

संदीप ओझा
संपादक

गौतमबुद्ध नगर सीट, ये जातियां हैं जीत की गारंटी

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट। यानी आपकी अपनी सीट। लोकसभा चुनाव में नोएडा सीट की लड़ाई हमेशा से दिलचस्प रही है। लेकिन 24 के चुनाव में करीब करीब एक बनाम सब की टक्कर है। एक तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा तो उनके खिलाफ दावेदारी ठोंक रहे हैं समाजवादी पार्टी से महेंद्र सिंह नागर और बहुजन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सोलंकी । महेश शर्मा के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है। हालांकि चुनावी बिसात पर ऊंट किस करवट बैठ जाए ये बताना नामुमकिन है। हालांकि सपा का अपने प्रत्याशी को लेकर स्टैंड अंतिम तक अस्थिर है, जो बीजेपी के लिए किसी बूस्ट से कम नहीं है, समाजवादी पार्टी ने पहले महेंद्र सिंह नागर फिर राहुल अवाना और एक ही चुनाव में तीसरी बार प्रत्याशी को बदलते हुए डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर पर फिर भरोसा जताया, जो किसी पार्टी के लिए असहजता की स्थित पैदा करती है। फिर भी गौतम बुद्ध नगर सीट पर कुछ जातियां ऐसी हैं जो चुनावी जीत की गारंटी मानी जाती हैं।

कौन कौन हैं विनिंग फैक्टर आइए विस्तार से जानते हैं । गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का इतिहास भी खंगालते हैं ।

स्वतंत्र सीट बनने पर बसपा ने फहराया झंडा

2009 में गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट का गठन किया गया और इसे सामान्य सीट कर दिया गया। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद इस लोकसभा क्षेत्र में नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। गौतमबुद्ध नगर जिला बसपा प्रमुख मायावती का गृह जनपद है। 2009 के संसदीय चुनाव में मायावती ने सुरेंद्र सिंह नागर को प्रत्याशी बनाया। स्वतंत्र लोकसभा सीट बनने के बाद यहां पहली बार हो रहे संसदीय चुनाव में जनता ने बसपा उम्मीदवार पर भरोसा जताया और नागर भारी मतों के साथ विजेता बने। भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा दूसरे नंबर पर और सपा के नरेंद्र भार्टी तीसरे नंबर पर रहे।

2014 में BJP ने हिसाब बराबर किया

पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार से सबक लेते हुए भाजपा ने इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा भी उसके लिए खुशी लेकर आया। 2014 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा ने भारी मतों से जीत हासिल की। वहीं, सपा पिछली हार का अंतर कम करते हुए तीसरे स्थान

से दूसरे स्थान पर पहुंची। इस चुनाव में बसपा ने अपने तात्कालीन सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का टिकट काट दिया और सतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया। इस बदलाव का खामियाजा बसपा को भुगतना पड़ा। पिछले चुनाव में बसपा ने जहां जीत हासिल की थी, वहीं इस चुनाव में वह तीसरे पायदान पर पहुंच गई।

ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर तय करते हैं जीत

19 के चुनावी आंकड़े बताते हैं कि। गौतमबुद्धनगर के करीब 23 लाख वोटरों में करीब करीब 16 लाख वोटर गांव में रहते हैं। इनमें ठाकुर वोटर 4 से 4.5 लाख के करीब हैं। ब्राह्मण वोटरों की तादाद करीब 4 लाख है। मुस्लिम 3.5 लाख, गुर्जर 3.5 से 4 लाख, दलित 3.5 लाख और अन्य वोटर 3 लाख हैं।

नए मतदाता निर्णायक

गौतमबुद्ध नगर में इस बार आम चुनावों में नए मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। 15 मार्च तक अपडेट किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा में 7,59,418, दादरी में 7,04,502 और जेवर में 3,67,046 मतदाता हैं । सिकंदराबाद में 3,97,500 सिकंदराबाद में 3,97,500 और खुर्जा में 3,91,574 मतदाता हैं ।

24,223 पहली बार मतदाता

बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को छोड़कर गौतम बुद्ध नगर जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 18,30,966 है । आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें 102 तीसरे लिंग के मतदाता, 10,502 दिव्यांग (अलग-अलग तरह से सक्षम) मतदाता,24,223 पहली बार मतदाता और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 26,353 मतदाता शामिल हैं ।

गौतम बुद्ध नगर सीट से पहले का इतिहास

1952 में हुए देश के पहले संसदीय चुनाव के वक्त गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। तब यह क्षेत्र बुलंदशहर लोकसभा सीट का हिस्सा था। 1962 में तीसरे लोकसभा चुनाव के दौरान खुर्जा लोकसभा सीट का गठन किया गया और इसे खुर्जा में शामिल कर दिया गया। उन दिनों देश भर में कांग्रेस का सिक्का चल रहा था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खुर्जा सीट पर 1962 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस की लहर में उसके प्रत्याशी कन्हैया लाल बाल्मीकी को भारी मतों से जीत मिली। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ समेत अन्य प्रमुख दलों को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

रावण का गांव और द्रोणाचार्य का आश्रम

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट में नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, खुर्जा विधानसभा सीटें आती हैं। गौतमबुद्ध नगर जिला 6 सितंबर 1997 को आस्तित्व में आया। ये जिला गाजियाबाद और बुलंदशहर को अलग करके बना था। कहा जाता है कि यहां के गुर्जरों के जानवर चराते हुए उन्होंने कई पुस्तकों का अनुवाद किया था। नलगढ़ा गांव में भगत सिंह ने भूमिगत रहते हुए कई बम-परीक्षण किए थे। वहां आज भी एक बहुत बड़ा पत्थर भगत सिंह की याद में सुरक्षित रखा हुआ है। पौराणिक मान्यताों में यहां रावण का जन्मस्थान और द्रोणाचार्य आश्रम भी बताए जाते हैं । ऐसा माना जाता है कि बिसरख रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव हुआ करता था । उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बिसरख पड़ा था । वहीं गौतमबुद्ध नगर के दनकौर कस्बे में श्री गुरु द्रोणाचार्य का प्राचीन मंदिर है। सैंकड़ों वर्ष पहले बना यह मंदिर भारत में विख्यात है। देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहां दर्शन करने आते हैं। प्राचीन काल में एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की शरण में गए थे।

सिल्की साहनी
ब्यूरो चीफ

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री बड़ा मुद्दा

लोकसभा चुनाव से पहले "नो रजिस्ट्री, नो वोट" के लगे बैनर

हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक आशियाना हो, उस घर को बनाने के लिए जीवन भर की कमाई घर खरीददार लगा देता है, लेकिन घर लेने के बाद भी उस पर उसका मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में हजारों फ्लैट आज भी ऐसे हैं, जहां फ्लैट का पजेशन मिल चुका है लेकिन फ्लैट मालिक को अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। यानि वहां अभी तक फ्लैट की रजिस्ट्री हुई ही नहीं है। ये मसला साल या फिर दो तीन साल का नहीं, कई ऐसे फ्लैट हैं, जहां सालों से फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। गलती बिल्डर की है या फिर प्राधिकरण की लेकिन इसका खामियाजा तो खरीददार ही भुगत रहे हैं जो सालों से बैंक का लोन चुका रहे हैं और उनके फ्लैट की रजिस्ट्री किसी सपने से कम नहीं है। जब बिल्डर धोखाधड़ी कर जाए और अधिकारी सिस्टम की दुहाई देकर उनकी ना सुनें तो आम लोगों के सामने एक ही रास्ता बचता है वो है उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि। चुनाव जब-जब आता है ये जनप्रतिनिधि इनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बताते हैं, इनकी समस्याओं को खत्म करने का वादा ही नहीं, टाइमलाइन भी फिक्स कर देते हैं, चुनाव खत्म होता है और जब ये जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो ये सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं।

मुद्दा वही पुराना लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। घर खरीदारों का आरोप है कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है, जबकि सरकार का कहना है कि उसने अमिताभ कांत कमेटी की सिफ़ारिशों को मंज़ूरी दी है, जिससे रजिस्ट्री होनी शुरू हो गई है। हकीकत क्या है,जानें इस रिपोर्ट में।
कितने फ्लैटों की रजिस्ट्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आज भी हजारों फ्लैट हैं, जिनकी रजिस्ट्री अभी तक शुरू नहीं हुई है। एनसीआर में करीब ढाई लाख ऐसे फ्लैट हैं जो इससे प्रभावित है, इसमें करीब एक लाख 20

हजार फ्लैट खरीददारों को मिल गये लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। चुनाव को देखते हुए 10 हजार से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए जोर-शोर से अभियान चलाया गया। प्राधिकरण का दावा है कि अगर बिल्डर ने 25 फीसदी तक रकम जमा कर दी तो अप्रैल तक 25 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। प्राधिकरण ने इसके लिए बिल्डर की जवाबदेही तय की है। तय रकम नहीं चुका पाने के चलते कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री बंद है।

अमिताभ कांत रिपोर्ट

गौतमबुद्ध नगर जिले में फ्लैटों की रजिस्ट्री की मांग को लेकर घर खरीददार पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। ये मामला संसद से लेकर विधानसभा में भी उठाया जा चुका है कि फ्लैट नहीं तो वोट नहीं। जिसके बाद शासन ने रजिस्ट्री की समस्या के समाधान के लिए अभिताभ कांत समिति का गठन किया था। जिसने विभिन्न सिफारिशें की थी इन सिफारिशों को प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी। जिसमें बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देते हुए कहा गया था कि उन्हें कुल बकाये का 25 फीसदी प्राधिकरण में जमा कराना होगा, जिसके बाद उसी अनुपात में रजिस्ट्री शुरू होंगी।

नो रजिस्ट्री, नो वोट

नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अलग-अलग सोसायटियों में ये बैनर फिर लगने लगा है कि नो रजिस्ट्री, नो वोट। यहां के लोग इन बैनरों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 46 की गार्डेनिया ग्लोरिया सोसायटी में निवासियों का कहना है कि चुनाव में वोट लेते वक्त नेता वादा करते हैं कि रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई झांकने तक नहीं आते हैं। बिल्डर का बकाया है, जिसे अथॉरिटी नहीं ले पाई, अब उनकी रजिस्ट्री रोक कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मूर्ति चौक के करीब स्थिति हिमालय प्राइड सोसाइटी में भी 300 ऐसे फ्लैट हैं, जिसमें एक टॉवर की उसमें ओसी ही नहीं आई है, इस सोसायटी में आधा से ज्यादा ऐसे फ्लैट हैं, जिनकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। इनके घर खरीददार भी

लोकसभा चुनाव से पहले अपने सोसायटी में नो रजिस्ट्री, नो वोट का बैनर चला चुके हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसायटियों में भी लोगों में नाराज़गी है। पिछले डेढ़ साल से रजिस्ट्री की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ है।

अमिताभ कांत की इन सिफारिशों को मंजूरी

- बिल्डरों को दो साल ज़ीरो पीरियड का लाभ दिया गया। यानी उन पर उस दौरान जो ब्याज लगा उससे राहत दी गई।
- बिल्डरों को 60 दिन में 25% राशि जमा कराने को कहा गया
- जो बिल्डर ये पैसा जमा करेंगे, वहां रजिस्ट्री शुरू होने की बात है
- लेकिन इसका फ़ायदा उन प्रोजेक्ट को नहीं मिल रहा है जिनका केस एनसीएलटी में है

कब तक ज़्यादातर घरों की रजिस्ट्री शुरू होगी, इस पर अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी से बात करने की कोशिश, लेकिन आचार संहिता की वजह से उन्होंने बात करने से मना कर दिया।

रचेंगे इतिहास

गौतमबुद्ध नगर जिले में लोकसभा का चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं। इस जिले में पांच विधानसभा सीटें हैं। जिसमें तीन गौतमबुद्ध नगर की सीट और दो बुलंदशहर की सीट शामिल हैं। दादरी, जेवर, नोएडा के अलावा खुर्जा और सिकंदराबाद भी गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। वैसे खुर्जा और सिकंदराबाद बुलंदशहर जिले में आते हैं। अगर गौतमबुद्ध नगर जिले की बात करें तो यहां की प्रमुख समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तरह बेहतर कनेक्टिविटी, बिल्डर-बायर्स, मेट्रो की कनेक्टिविटी, किसानों की मांगें शामिल हैं। दादरी विधानसभा में रहने वाले लोग लोकसभा चुनाव को लेकर कितने संतुष्ट हैं, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले निवासी मेट्रो की मांग और रजिस्ट्री, पजेशन को लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं, इसी पर हमारे संवाददाता साजिद अली ने दादरी विधायक तेजपाल नागर से खास बातचीत की।

साजिद- लोकसभा चुनाव में बीजेपी किस तरह जनता के बीच जा रही है।

तेजपाल सिंह नागर- बीजेपी ने बूथ व्यवस्था तक तैयारी कर चुकी है। पहली बात तो ये कि बीजेपी का मकसद है एक-एक वोट बूथ तक पहुंचे और बीजेपी को अपना वोट दे इसके लिए हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसकी व्यवस्था पार्टी ने पूरी तरह से कर ली है। इस बार हम 400 सीट पार कर रहे हैं इसके साथ हमारा प्रयास ये भी है कि दादरी विधानसभा में बीजेपी को अधिक से अधिक मार्जिन में वोट मिले। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी की जो तीन बड़ी जीत होगी उसमें एक गौतमबुद्ध की सीट भी शामिल होगी।

साजिद- विधायक जी क्योंकि आपकी पार्टी से लगातार दो बार महेश शर्मा सांसद रहे हैं, तीसरी बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर दांव लगाया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस बात से नाराजगी है कि सेक्टर की तर्ज पर गांवों में काम नहीं हुआ है।

तेजपाल सिंह नागर- ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ शहरों के विकास पर ध्यान दे रही है। शहर के साथ गांवों में भी विकास की रफ्तार तेज है। अगर दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दादरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की परियोजनाओं पर काम जारी है। जांचरे से लेकर वीरपुरा, खंदेड़ा, अंदपुर, जीटीरोड, चकरपुर होते हुए ग्रेटर नोएडा तक चौड़ी सड़क बन रही है। यहां निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसी तरह खटाना के पुल से लेकर फूलपुर, नई बस्ती, जीटी रोड, बील और रामगढ़ होते हुए ग्रेटर नोएडा तक को चौड़ी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस बार शहरों की तुलना में गांवों का उत्साह कम नहीं होने वाला है। यहां लोग भी बीजेपी के कार्यकाल से बेहद प्रशन्न हैं। इस बार गांवों से बीजेपी को वोट प्रतिशत भी बढ़ने वाला है।

साजिद- विधायक जी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा विषय बन गया है। वैसे यहां के लोगों के सामने रजिस्ट्री, पजेशन पहले से बहुत बड़ा चिंता का विषय है।

तेजपाल सिंह नागर- कुछ लोगों ने प्रदर्शन को धंधा बना लिया है। बिना विश्वास के कोई काम नहीं चलता। लोगों को पहले ये भी विश्वास नहीं होता था कि बिल्डर, बॉयर की समस्या खत्म हो जाएगी, जिस पर हमारी सरकार ने प्राथमिकता के साथ काम किया और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। मोदी और योगी हैं तो मुमकिन है विश्वास रखिए ये भी समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी।

WEB Cadence INDIA

SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY

Our Best Service

- Lead Manegment
- Help desk Manegment
- QR Code Generation
- School Manegment
- Inventory Manegment

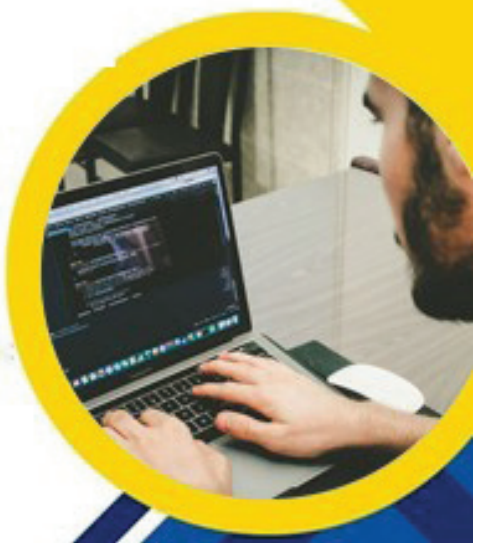

+91 7982133887 www.webcadenceindia.com asha@webcadenceindia.com

Mailing Solution
A Unit of Webcadence

Email Marketing

- Domain
- Bulk SMS/ Bulk Email
- Bulk Whatsapp
- Coporate Email

+91-98715-55245 admin@webcadenceindia.com www.mailingsolutions.in

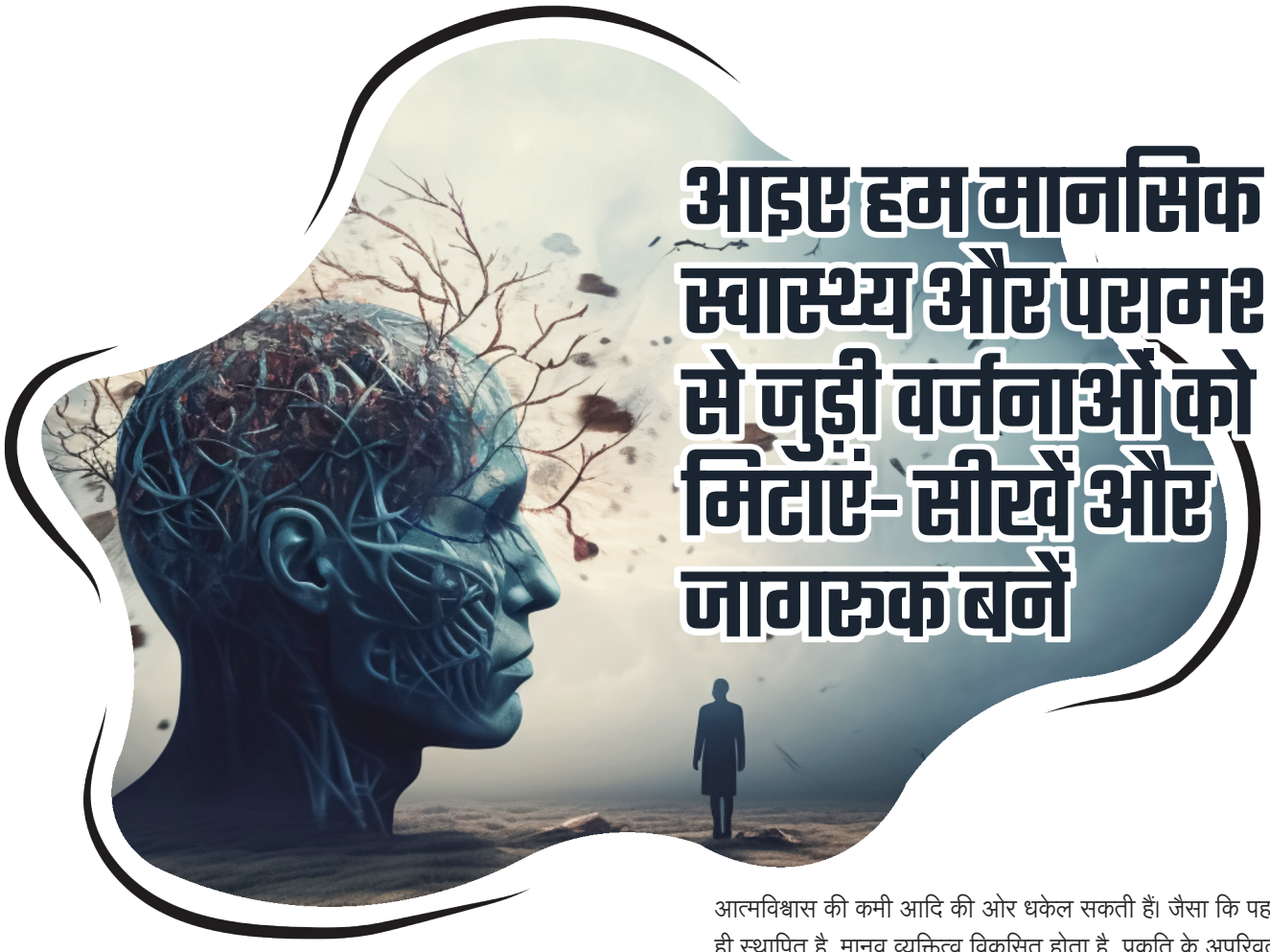

आइए हम मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श से जुड़ी वर्जनाओं को मिटाएं- सीखें और जागरुक बनें

मेघना सिंह
जॉइंट हेड, (को-फाउंडर)
पीस ऑफ़ माइंड काउंसलिंग सर्विस, नॉएडा

पूरी दुनिया के लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पिछले पांच वर्षों में सामूहिक रूप से पहले की तुलना में शायद कई गुना अधिक अनुभव किया है, बात की है और शोध किया है, खासकर कोविड महामारी के बुरे प्रभावों के कारण। हमारे देश भारत में हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के मामलों में 30 से 40% की वृद्धि देखी गई है। डेटा चिंताजनक है. हमें यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी और उचित उपाय करने होंगे कि अधिक से अधिक

मानसिक स्वास्थ्य रोगियों का समय पर इलाज हो और कई अन्य की गंभीर समस्याओं के लक्षण दिखने से पहले ही जांच की जाए।

हमें इसका एहसास नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक तनाव, संघर्ष और निराशाएं हमें कम प्रदर्शन, खराब कामकाज, बार-बार होने वाली शारीरिक बीमारियों, आत्मविश्वास की कमी आदि की ओर धकेल सकती हैं। जैसा कि पहले से ही स्थापित है, मानव व्यक्तित्व विकसित होता है, प्रकृति के अपरिवर्तनीय मिश्रण के आधार पर (यानी हमारा आनुवंशिक तंत्र जिसे हम विरासत के कारण लेकर पैदा हुए हैं) और पोषण (यानी हमारे पर्यावरण ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया और हमारी मानसिकता को कैसे प्रभावित किया आदि)।

हालाँकि, ऐसा अधिक से अधिक प्रतीत होता है कि जिस वातावरण में हम रहते हैं वह यह स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बनते हैं।

एक मनोवैज्ञानिक और एक चौकस व्यक्ति के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करती हूं कि अब समय आ गया है कि हम उठे और स्वीकार करें कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे यहीं रहेंगे, कि इसे अलगाव में संबोधित नहीं किया जा सकता है और यदि इसे जल्द से जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो परिणाम अपरिवर्तनीय हो सकते हैं।

आइए हम अपनी समझ को फिर से स्थापित करें कि वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य क्या है और पेशेवर परामर्श हमें अपनी मानसिक स्वच्छता बनाए रखने में कैसे सक्षम बना सकता है।

'अच्छा मानसिक स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक कल्याण' क्या है?
सीधे शब्दों में कहें तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति इष्टतम स्तर पर कार्य करने में सक्षम है, तनाव और तनाव से बाहर आने में सक्षम है, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, आलोचना और

निर्णय का प्रबंधन करने में सक्षम है और निरंतर आत्म-विकास की दिशा में काम करने में सक्षम है।

विभिन्न कारक जो मानसिक भलाई को प्रभावित करते हैं

जैविक: आनुवंशिक रूप से यदि कोई नकारात्मक रूप से उन्मुख है या भयभीत है या उसे नियमित चिकित्सा समस्याएं हैं तो यह निश्चित रूप से उस पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव डाल सकता है। जन्म से विकलांग व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं।

सामाजिक: किसी भी प्रकार का भेदभाव, कलंक, अपमान, धमकाना, व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक आघात का कारण बन सकता है।

मनोवैज्ञानिक: जीन या वंशानुगत या आघात, दुर्व्यवहार, दुर्घटनाओं, मृत्यु, व्यसनों और प्राकृतिक आपदाओं जैसे पर्यावरणीय कारकों से प्राप्त हार्ड कोर विकार हो सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिक, न्यूरोटिक और या व्यक्तित्व विकारों के रूप में प्रकट होते हैं।

शारीरिक: दीर्घकालिक शारीरिक बीमारियाँ, अंगों की हानि (जन्म या दुर्घटना से), कैंसर, ऑटो इम्यून रोग आदि जैसी लाइलाज बीमारियाँ भी मानसिक तनाव को ट्रिगर कर सकती हैं जिससे मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है।

सोशल मीडिया: आभासी दुनिया वास्तव में अपने आप में एक दुनिया है जिसने हमारी इस पीढ़ी को अपनी चपेट में ले लिया है और हम हर गुजरते दिन के साथ नई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की खोज और परिभाषा कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव मानस के साथ बिल्कुल नए तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं जो शोध समुदाय में एक बहुत ही गर्म विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उछाल मुद्दों की जटिलता और गंभीरता को कई गुना बढ़ा रहा है।

आज के समय में मदद लेने की आवश्यकता सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों है?

हर जगह सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है। हम स्वयं को और अधिक अकेला पाते जा रहे हैं। हम पहले से कहीं अधिक व्यक्तिवादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने और प्रबंधन के विभिन्न पुराने तरीके निरर्थक हो गए हैं। समय की कमी सभी के लिए है। किसी पर भरोसा करना किसी के साथ रात गुजारने से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. कुल मिलाकर समाज अधिक विचारशील और निर्णयात्मक हो गया है। डेटा, सूचना तक पहुंच और अत्यधिक प्रदर्शन विकास और प्राकृतिक विकास की जैविक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है।

यह सब इस तथ्य का संकेत है कि जब कोई संघर्ष कर रहा होता है, जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा होता है, सब कुछ खुद से प्रबंधित करने की कोशिश कर रहा होता है, तो किसी पेशेवर के पास पहुंचना ही इसका उत्तर होता है। परिवार, रिश्तेदार और दोस्त केवल समर्थन, सहानुभूति, सलाह दे सकते हैं लेकिन आपके मुद्दों के प्रभाव के विस्तार को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। एक प्रशिक्षित पेशेवर आपकी बात सुनने में सक्षम होता है, आपकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखता है, बिल्कुल गैर-निर्णयात्मक होता है, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान देता है और आपको अपने बारे में बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाता है। बहुत सारे तनावपूर्ण मुद्दों, मानसिक विकारों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के समाधान के लिए वास्तव में पेशेवर हस्तक्षेप और उपचार की एक सूचित लाइन की आवश्यकता होगी।

पेशेवर मदद कब लेनी है?

निम्नलिखित संकेत और लक्षण किसी व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करने के संकेतक हैं

1. **लक्षणों और उनकी गंभीरता में वृद्धि:** जिन व्यक्तियों को पहले से ही तनाव, चिंता है या वे किसी करीबी की मृत्यु जैसी जीवन की प्रतिकूलताओं से जूझ रहे हैं, वे देख सकते हैं कि उनके लक्षण गंभीर होते जा रहे हैं और आपको उन्हें प्रबंधित करना मुश्किल हो रहा है, तो तुरंत मदद लें।

2. **स्वयं की देखभाल:** स्नान, कंघी करना, कपड़े धोना, कपड़े बदलने जैसी सामान्य दैनिक गतिविधियों के साथ स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ होना यानी व्यक्तिगत स्वच्छता से समझौता करना मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का संकेत देता है।

3. **रुचि कम होना:** यदि आपने उन गतिविधियों में रुचि लेना बंद कर दिया है जिन्हें आप पहले करना पसंद करते थे। काम करने के लिए प्रेरणा की कमी ख़राब मानसिक स्वास्थ्य का कारण हो सकती है

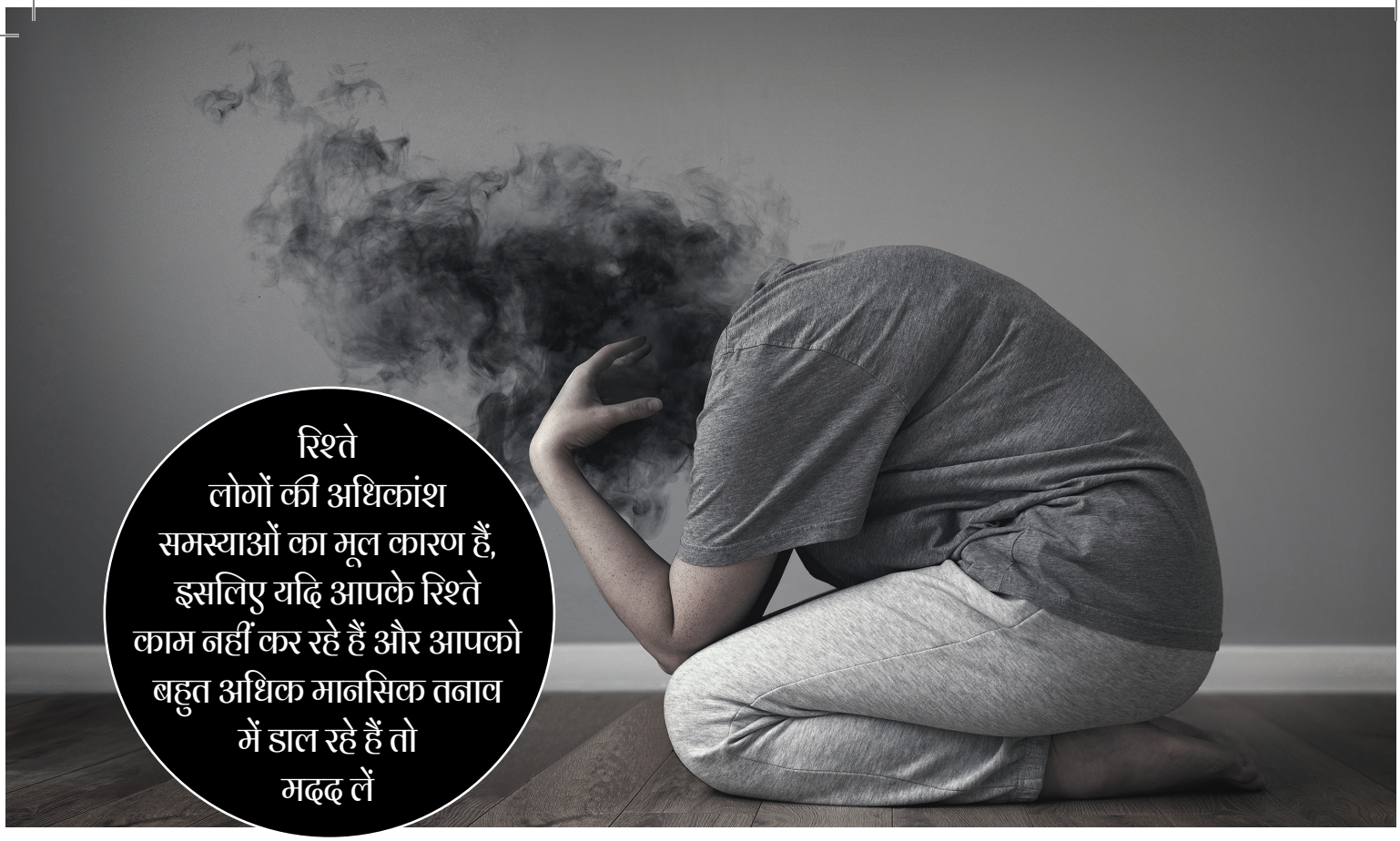

4. **अत्यधिक सोचना, नकारात्मक भावनाओं का बढ़ना/विकृत सोच:** यदि स्वयं के साथ रचनात्मक आंतरिक संवाद बनाए रखने में असमर्थ हैं। या स्वयं और आसपास की दुनिया के लिए अत्यधिक नकारात्मकता, हर समय आलोचनात्मक महसूस करना, अनजाने में रोना तो निश्चित रूप से मदद लें।5. नींद न आना, वजन घटना या बढ़ना, सुस्ती, लगातार अगर ऐसा पिछले कम से कम 15 दिन या उससे अधिक समय से हो रहा है। फिर मदद मांगें।

6. **विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन:** पदि आपको लगता है कि विभिन्न स्थितियों में आपका व्यवहार बदल रहा है, जैसे बढ़ती चिड़चिड़ापन, क्रोध का विस्फोट, झगड़े, भावनात्मक गड़बड़ी, सामाजिक सेटिंग्स से हटना तो किसी पेशेवर की मदद लें।

7. **कार्यस्थल या स्कूल में लगातार खराब प्रदर्शन:** तुरंत अपने परामर्शदाता से बात करें।

8. **विघटनकारी रिश्ते:** यह देखा गया है कि रिश्ते लोगों की अधिकांश समस्याओं का मूल कारण हैं, इसलिए यदि आपके रिश्ते काम नहीं कर रहे हैं और आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव में डाल रहे हैं तो मदद लें।

9. **स्वयं और परिवेश से कटा हुआ या भटका हुआ महसूस करना-** तुरंत किसी मनोवैज्ञानिक से बात करें

10. **अन्य कारक जैसे:** मूड में बदलाव, मतिभ्रम, बार-बार आत्मघाती विचार, शोक, दुर्व्यवहार, धमकाने जैसे दर्दनाक अनुभव भी तुरंत मदद लेने के संकेतक हैं।

उपरोक्त सभी लक्षण और संकेत बताते हैं कि आप मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इसलिए तुरंत पेशेवर मदद लें। पेशेवर आपकी बात सुनने और आपके लिए बिंदुओं को मापने और जोड़ने में सक्षम होगा। इसके साथ ही आप अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद के लिए विभिन्न उपचारों का उपयोग करेंगे। इससे आपके मुकाबला करने के कौशल में वृद्धि होगी और आत्म-जागरूकता बढ़ेगी।

विभिन्न समस्याओं के लिए सभी आयु समूहों से निपटने वाले एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, यह मेरा अवलोकन और सभी के लिए सिफारिश है कि यदि संभव हो, तो महीने में कम से कम एक बार किसी पेशेवर से बात करें, भले ही आपमें उपरोक्त लक्षण हों या नहीं। जो लोग उपरोक्त में से कोई भी लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, वास्तव में इसका मतलब है कि उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की है और उनके अधिकांश कौशल वर्तमान में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं।

इसलिए सलाह दी जाती है कि जैसे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करते हैं और नियमित रूप से जिम जाते हैं, वैसे ही उपरोक्त संकेतों और लक्षणों को दूर रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से नियमित रूप से मिलें और बात करें।

मानसिक स्वास्थ्य एक आवश्यकता है और हम सभी को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है!

THE STREET VIEW
THE PLEASURE OF
VARIETY ON YOUR PLATE
COUNT THE MEMORIES NOT
THE CALORIES
More Information
9910625795
More Information
www.thestreetviewrestro.com

THE STREET VIEW
RESTAURANT
What Are You
Craving For ?
KURKURE MOMOS
NOODLES
FRENCH FRIES
FRIED RICE
More information
9910625795
More information
www.thestreetviewrestro.com

सांसदों का टिकट काटने में बीजेपी ने किया शतक पार

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। आर्टिकल लिखे जाने तक बीजेपी ने कुल 6 लिस्ट जारी किये हैं। पार्टी ने अभी तक जो लिस्ट जारी की उसमें मौजूदा 291 सांसदों में से 103 सांसदों के टिकट काट दिये गये हैं। इस लिस्ट में जिनके टिकट काटे गये हैं, उनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। 10 ऐसे सांसदों के भी पार्टी ने टिकट काट दिये हैं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं। इसके पीछे तर्क ये सामने आ रहा है कि पार्टी उन नेताओं से छुटकारा पाना चाहती है जिनके बड़बोलेपन और विवादित बयान से बवाल खड़ा हुआ। इनमें गोड़से को महान बताने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा, समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने वाले प्रवेश वर्मा, संसद में अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद के खिलाफ टिप्पणी करने वाले रमेश विधूड़ी और पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधने वाले वरुण गांधी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक, प्रताप सिम्हा, वीके सिंह, अनंत हेगड़े, अश्विनी चौबे, हर्षवर्धन, गौतम गंभीर जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं।

किस राज्य में कितने सांसदों के कटे टिकट

अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने अभी तक 34 फीसदी मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। जिसमें गुजरात नंबर वन है। यानि हर तीन में से एक वर्तमान सांसद के टिकट पार्टी ने काट दिये हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में सबसे अधिक सांसदों पर गाज गिरी है। बीते चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा ने 26 में से 14 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं, दिल्ली में 7 में से 6 सांसद तो उत्तर प्रदेश में पांचवीं सूची में 9 सांसद टिकट पाने में नाकाम रहे। ओडिशा में चार, बिहार, कर्नाटक और झारखंड से तीन-तीन सांसदों का पत्ता कट चुका है। जब 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई थी, तब ऐसा लगा था कि पार्टी निवर्तमान सांसदों के लिए दिल बड़ा करेगी, पहली सूची में 33 सांसदों का टिकट कटा था। तब यूपी के सभी 41 सांसद टिकट हासिल करने में कामयाब हुए थे।

साल 2019 में क्या था आंकड़ा?

बीजेपी ने साल 2019 में अपने 282 सांसदों में 119 टिकट काटे थे, यानि करीब 42 फीसदी सांसदों को दोबारा टिकट नहीं मिला था। इसके पीछे एंटी इंकम्बेंसी बड़ा मसला हो सकता है। इस बार भी करीब 34 फीसदी वर्तमान सांसदों के टिकट अब तक काटे जा चुके हैं, जो नई जारी होने वाली लिस्ट के साथ ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।

दिल्ली फतह करना बड़ी चुनौती

बीजेपी ने दिल्ली में अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी ने अपने 6 वर्तमान सांसदों के टिकट नहीं दिया है, यहां पर सिर्फ मनोज तिवारी ही अपनी टिकट बचाने में कामयाब हुए हैं। दो बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट काटकर यहां पर प्रवीण खंडेवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी दिल्ली में दो बार से सांसद परवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली से रमेश विधूड़ी की जगह रामवीर सिंह विधूड़ी, नई दिल्ली लोकसभा सीट से मीनाक्षी लेखी की जगह दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में पार्टी ने उतारा है। बात करें उत्तर पश्चिम दिल्ली की तो यहां हंसराज हंस की जगह योगेश चंदोलिया को टिकट दिया गया है। वहीं पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि उत्तर पूर्वी सीट से एक बार फिर मनोज तिवारी पर पार्टी ने भरोसा कायम रखा है।

गुजरात में क्यों नहीं बनी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात की बात करें तो यहां लोकसभा की 26 सीटें हैं, बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। यहां पर 26 में से 14 नए चेहरों को पार्टी ने इस बार जगह दी है। मोदी सरकार में दो केंद्रीय राज्य मंत्रियों का टिकट भी काट दिया गया है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों की जगह दो नए चेहरे को उम्मीवार पार्टी ने बनाया है। दर्शनाबेन जरदोश की जगह पर सूरत बीजेपी के महामंत्री मुकेश दलाल को टिकट दिया गया है, जबकि डॉक्टर महेंद्र मुंजपरा की जगह पर जिला पंचायत के पूर्व प्रमुख रहे चंदूभाई सिहोर चुनाव लड़ेंगे। चंदूभाई साल 2017 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे।

ओम प्रकाश सिंह
विशेष संवाददाता

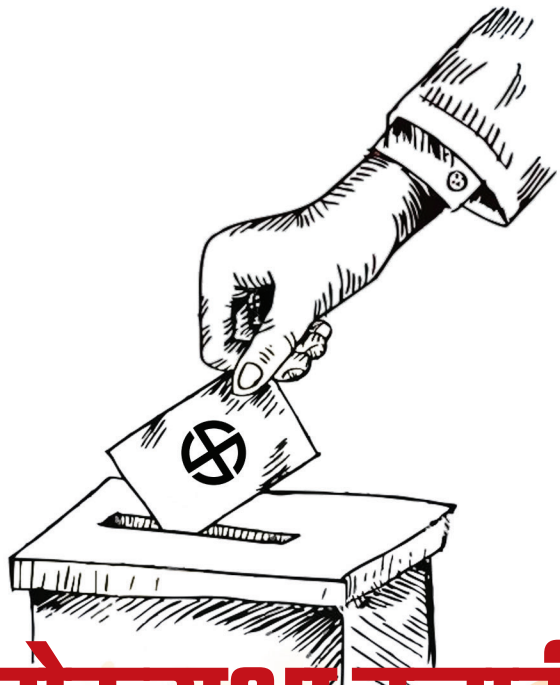

भारतीय लोकसभा चुनावी इतिहास

देश में 18वीं बार आम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ आचार संहित भी लागू है। इस बार भी 7 चरणों में हो रहे चुनाव को लेकर सियासत की बिसात बिछ चुकी है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीवारों के मैदान में उतार दिया है। वादों और घोषणाएं जारी है। जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत का 'हैट्रिक' लगाने के लिए पूरे जोश-खरोस में लग गई है। भाजपा इस बार भी बहुमत हासिल कर फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद कर रही है। वहीं, विपक्ष एक जुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में जुटा है। हांलाकि चुनाव से पहले बना विपक्षियों का गठबंधन 'इंडिया' चुनाव की घोषणा होने से पहले बिखर गया। विपक्षी गठबंधन में कुछ ही पार्टियां बची हैं। अब इनके सहारे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। फिलहाल ये तो नतीजे बताएंगे कि 'ऊंट किस करवट बैठेगा'।

भारतीय लोकसभा चुनाव का इतिहास

भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। हालांकि इसके पहले जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ। इसमें कुल 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने इसमें बहुमत प्राप्त किया। इस बार भी पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45 प्रतिशत मत मिले। इसके बाद 1957 और 1962 चुनाव में भी कांग्रेस को बहुमत मिला और जवाहलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने जो कार्यकाल खत्म होने तक बने रहे।

जनता पार्टी की सत्ता में एंट्री

1967 और 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही जीत मिली और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इमर्जेंसी के बाद चुनाव 1977 में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया। जिसके मोरारजी देसाई बने। इसके बाद 1980 में कांग्रेस ने कमबैक किया और बहुमत हासिल करते हुए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। 1984 चुनाव यह चुनाव दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और कांग्रेस पार्टी को बड़ी बहुमत मिला और राजीव गांधी प्रधानमंत्री चुने गए।

अब तक चुने गए देश के प्रधानमंत्री

पंडित जवाहरलाल नेहरु (1947-1964): भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरु, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संघर्ष के समय बड़ा योगदान दिया। उनके कार्यकाल में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ और प्रस्तुति की संस्कृति को प्रोत्साहन मिला।

लाल बहादुर शास्त्री (1964-1966): उनके कार्यकाल में भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ और "जय जवान, जय किसान" के नारे को आम लोगों की भावनाओं का प्रतीक बनाया।

इंदिरा गांधी (1966-1977, 1980-1984): इंदिरा गांधी ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में गरीबी हटाओ अभियान, बांग्लादेश के स्थापना, आपातकाल आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं थीं।

राजीव गांधी (1984-1989): राजीव गांधी के कार्यकाल में भारत में तकनीकी और आर्थिक विकास को महत्व दिया गया।

पी वी नरसिम्हा राव (1989-1991): वह भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधार और लोकतांत्रिक नवाचार हुए।

अटल बिहारी वाजपेयी (1996, 1998-2004): अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में नए दरवाजे खोले और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मनमोहन सिंह (2004-2014): मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास हुआ और विश्व बाजार में भारत की पहचान मजबूत हुई।

नरेंद्र मोदी (2014-वर्तमान): नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अनेक कदम उठाए हैं जैसे अटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत आदि। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ.

राज्यों में लोकसभा सीटें

अंडमान और निकोबार
1 सीट

अरुणाचल प्रदेश
2 सीटें

असम
14 सीटें

बिहार
40 सीटें

चंडीगढ़
1 सीट

छत्तीसगढ़
11 सीटें

दादरा और नगर हवेली
1 सीट

दमन और दीव
1 सीट

दिल्ली
7 सीटें

गोवा
2 सीटें

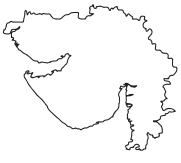

गुजरात
26 सीटें

हरियाणा
10 सीटें

हिमाचल प्रदेश
4 सीटें

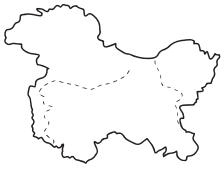

जम्मू और कश्मीर
6 सीटें

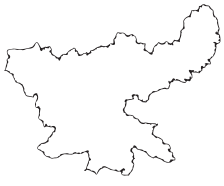

झारखंड
14 सीटें

कर्नाटक
28 सीटें

केरल
20 सीटें

मध्य प्रदेश
29 सीटें

महाराष्ट्र
48 सीटें

मणिपुर
2 सीटें

मेघालय
2 सीटें

मिजोरम
1 सीट

नागालैंड
1 सीट

ओडिशा
21 सीटें

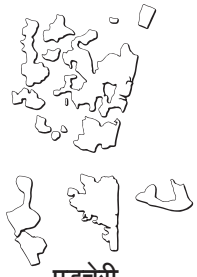

पुडुचेरी
1 सीट

पंजाब
13 सीटें

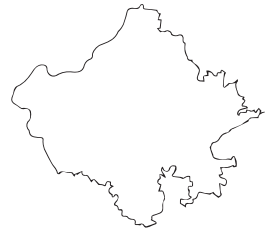

राजस्थान
25 सीटें

सिक्किम
1 सीट

तमिलनाडु
39 सीटें

तेलंगाना
17 सीटें

त्रिपुरा
2 सीटें

उत्तराखंड
5 सीटें

उत्तर प्रदेश
80 सीटें

पश्चिम बंगाल
42 सीटें

झारखंड
14 सीटें

लोकसभा चुनाव में भाजपा की भूमिका

1991 चुनाव भारतीय राजनीति में बड़े परिवर्तन का कारण बना। क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल होने के बावजूद एक स्वतंत्रता प्रिय दल, भारतीय जनता पार्टी, की भूमिका मजबूत हुई। 2014 चुनाव: इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। 2019 चुनाव: इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया।

2019 लोकसभा चुनाव पर एक नजर

सत्रहवीं लोक सभा के गठन के लिए 2019 में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में अयोजित कराये गये। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किये। जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और अपने पूर्ण बहुमत बनाये रखा। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीतीं। भाजपा ने 37.36% वोट हासिल किए। जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60.37 करोड़ वोटों का 45% था। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीतीं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें जीतीं। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीतीं।

भारत की सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डॉ. प्रियंका सिंह
प्रो. एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा

प्रस्तावना :

भारत एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, जातियों और जातीय समूहों के लोग अपनी जीवंतता और विविधता के साथ रहते हैं। हमारे देश में प्रत्येक जातीय समूह की अपनी मूल कहानी और अनूठी परंपराओं और संस्कृति का अपना समूह है। भारत को एक समृद्ध प्राकृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। इसका कारण देश का विशाल भौगोलिक क्षेत्र है। विशाल भौगोलिक विस्तार के कारण देश के विभिन्न भागों की जलवायु परिस्थितियाँ भिन्न हैं। जबकि उत्तरी क्षेत्र बेहद ठंडी जलवायु का अनुभव करते हैं, दक्षिणी छोर पर उच्च तापमान दिखाई देता है।

जलवायु परिस्थितियों और ज़मींदारों की भारी असमानता के कारण, भारत में समृद्ध जैव विविधता है। इसमें विभिन्न प्रकार की लुभावनी भूवैज्ञानिक संरचनाओं को भी समाहित किया गया है।भारतीय विरासत कई शताब्दियों पहले की है। यह विशाल और जीवंत है। हमने अपनी संस्कृति और परंपरा को शुरू से ही महत्व दिया है और इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खूबसूरती से संरक्षित किया है। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी प्रगति की है और हम कितनी दूर तक पहुँचने की योजना बना रहे हैं, हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वे हम में अंतर्निहित हैं और हमारे लिए एक अविभाज्य हिस्सा हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। हमारे देश में कई जातियों, धर्मों और पंथों के लोग रहते हैं। इनमें से प्रत्येक जाति और धर्म के अपने रीति-रिवाज और परंपराएं हैं। प्रत्येक धार्मिक समूह द्वारा पालन की

जाने वाली संस्कृति में गहरी अंतर्निहित जड़ें हैं और इसका अटूट विश्वास है।

भारतीय परंपराएँ:

भारतीय रीति-रिवाज और परंपराएँ हमें विनम्र बने रहने, दूसरों का सम्मान करने और समाज में सद्भाव से रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हम अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। ये हमारी जीवन शैली में अंतर्निहित हैं और हमारे द्वारा लिए गए कई निर्णय हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों पर आधारित हैं। इन्हें पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया जाता है। भारतीय त्योहार देश की संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब हैं। एक पारंपरिक पैटर्न है जिसमें ये मनाए जाते हैं। इस पैटर्न का पालन प्राचीन काल से किया जा रहा है। ये समारोह हमारे प्रियजनों से मिलने और शुभकामनाएं देने और सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक शानदार तरीका है। ये हमारी समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं।

हमारी विरासत का संरक्षण :

भारतीय अपने रीति-रिवाजों और परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं। हमें बचपन से ही एक निश्चित तरीके से कार्य करना सिखाया जाता है और कुछ प्रथाओं में लिप्त होने से बचना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति के प्रति सहजता बने रहें। भारतीय रीति-रिवाज और परंपराएं सुंदर हैं। वे हमें विनम्र बने रहने और दूसरों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें उन्हें संरक्षित करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी उतनी ही वृद्धि करनी चाहिए जितनी वे एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें।

हमारी धरोहरों को संरक्षित करना :

भारत प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के विरासत स्थलों को समाहित करता है। कुछ सबसे खूबसूरत विरासत स्थल हमारे देश के हैं। उनकी खूबसूरती को दुनिया भर में सराहा गया है। हालांकि, इनमें से कई समय के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ मानवीय लापरवाही इन खूबसूरत विरासत स्थलों की गिरावट में योगदान दे रही है।

इनमें से कई अपना मौका खो रहे हैं और आने वाले समय में कम हो सकते हैं यदि हम उन्हें संरक्षित करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत का प्रतिबिंब हैं और हमें इन्हें नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा, ये साइटें देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती हैं क्योंकि वे दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन विरासत स्थलों को संरक्षित करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। हमें इस दिशा में जो कुछ भी कम हो सकता है, उसमें भी योगदान देना चाहिए।

नई पीढ़ी के लिए भारतीय विरासत का मूल्य :

हमारी सांस्कृतिक विरासत सदियों से बरकरार है लेकिन मौजूदा समय में इसका आकर्षण कम होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक विरासत को उतना महत्व नहीं देती।

हमारे समाज ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त बदलाव देखे हैं। अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के उपनिवेशण ने पश्चिमी संस्कृति को हमारे देश में लाया। सदियों पुरानी परंपराएं बदलने लगीं। आज, भारतीय पोशाक पश्चिमी संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित है। गुरुकुल की हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को नए तरह के स्कूलों से बदल दिया गया था और उस युग में कई अन्य बदलाव लाए गए थे। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा।

हमारे समाज ने कई बदलाव देखे हैं। उदाहरण के लिए, हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली नई परमाणु परिवार प्रणाली के लिए रास्ता दे रही है। प्रौद्योगिकी में वृद्धि और इंटरनेट और स्मार्ट फोन के आगमन ने हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर कर दिया है। पश्चिमी संस्कृति देश के युवाओं को लुभाती है और उनमें से ज्यादातर हमारी संस्कृति और परंपराओं को देखते हैं।

युवा पीढ़ी अपनी दुनिया में इतनी तल्लीन है और इतनी आत्म केंद्रित हो गई है कि वह बड़ों द्वारा दिए गए सांस्कृतिक मूल्यों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है।

भारतीय विरासत के लिए प्यार और सम्मान का आह्वान करना:

युवा पीढ़ी में भारतीय विरासत के लिए प्रेम का आह्वान करना बड़ों का कर्तव्य है। यह शुरू से ही किया जाना चाहिए तभी हम अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित कर सकते हैं।

हमारी विरासत के लिए प्यार का इजहार करने का एक तरीका है युवा पीढ़ी को हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित कराना। इससे उनके अंदर गर्व की भावना लाने में मदद मिलेगी और वे परंपरा को जारी रखने के लिए प्रेरित होंगे और नई पीढ़ी के लिए भी इसे पारित करेंगे। इसके लिए शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों के सामूहिक प्रयास की जरूरत है।

निष्कर्ष :

भारतीय विरासत अपनी विशालता के लिए जानी जाती है। इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी स्मारक विरासत, हमारा साहित्य और कला के विभिन्न कार्य शामिल हैं। हमारी विरासत कई सदियों पहले की है। समय के साथ हमारे दोनों मूर्त और अमूर्त विरासत दूर होते जा रहे हैं। हमें अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और इसे अपनी भावी पीढ़ियों के लिए पारित करने के लिए हमारी जिम्मेदारी के रूप में लेने की आवश्यकता है।

युवा पीढ़ी को न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना चाहिए, बल्कि हमारे देश की स्मारक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में भी प्रगतिशील होना चाहिए। हमारी संस्कृति, परंपरा, स्मारक, साहित्य और विभिन्न कलाएं हमारी विरासत का हिस्सा बनती हैं। इन्हें दुनियाभर में सराहा गया है। हमें ऐसी जीवंत संस्कृति वाले देश का हिस्सा होने पर गर्व है।

हर रंग में छुपी है खुशियों की बात...

NOW NOIDA अपडेट

सत्य से साक्षात्कार

पत्रिका सदस्यता प्रपत्र

भारत के व्यक्तियों के लिए वार्षिक सदस्यता: ₹440 ☐

भारत के बाहर और कॉर्पोरेट दरें: ₹2,000 ☐

Name .....

Address.....

.....

.....

.....

Postcode.....

Telephone.....

Email.....

कृपया चेक या पोस्टल ऑर्डर करें

MBI Digital Private Limited को देय।

MBI
Direct From Factory

FASHION COLLECTION

SPECIAL OFFER

USE COUPON CODE:

FLAT20

UPTO
20%
OFF

SHOP NOW

sales@madebyindia.com

+91 07011412854